भारतीय वैश्विक परिषद

सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन कीओर

आईसीडब्ल्यूए में एससीओ निवासी शोधकर्ताओं के मंतव्य

भारतीय वैश्विक
परिषद
सप्रू हाउस, नई

भारतीय
वैश्विक
परिषद

सुरक्षित
शंघाई
सहयोग संगठन
की ओर

आईसीडब्ल्यूए में एससीओ के मंतव्य

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली

जून 2023

© आईसीडब्ल्यूए जून 2023

अस्वीकरण: इन लेखों में विचार, विश्लेषण और अनुशंसा व्यक्तिगत हैं और आईसीडब्ल्यूए के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

विषय-वस्तु

आमुख 5

लेखक 7

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एससीओ की भूमिका

गुलडेन कास्करबायेवा 9

शंघाई सहयोग संगठन सूचना सुरक्षा
सहयोग:वर्तमान स्थिति और नीति विकल्प

ज़ौ झेंगशिन 19

साझा विषयों की खोज, विविधता को अंगीकार करना: एससीओ
देशों का सामान्य भविष्य

कारगुलोव बटीर-मुखम्मद आज़मतोविच 29

शंघाई सहयोग संगठन एक नए भू-राजनीतिक
वातावरण में: अखिल-यूरेशिया सहयोग की संस्था बनना?

दिमित्री पावलोविच नोविकोव 37

एक बहुआयामी रणनीति को आगे बढ़ाना: डिजिटल युग
में नशीली दवाओं की तस्करी की चुनौतियों के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया

रहीमोव फरीदुन 53

एससीओ में क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को सुदृढ़ करना

दवलातोव कमरोनबेक संजरबेक उगली 65

भारत ने 2022-2023 की अवधि के लिए राष्ट्राध्यक्षों की शंघाई सहयोग संगठन परिषद की अध्यक्षता पहली बार ग्रहण की। भारत की एससीओ अध्यक्षता जुलाई 2023 में एक शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होगी। भारत की एससीओ अध्यक्षता का विषय "एक 'सुरक्षित' एससीओ की ओर" है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 एससीओ शिखर सम्मेलन में पहले व्यक्त किया था। एससीयूआरई का अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संयोजकता, एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए सम्मान, और पर्यावरण। यह क्षेत्र के प्रति भारत की समग्र दृष्टि को शामिल करता है और *'वसुधैव कुटुम्बकम'* के भारतीय लोकाचार को दर्शाता है-विश्व एक परिवार है।

अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत ने कई मंत्रिस्तरीय और आधिकारिक बैठकें, संगोष्ठी, सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और विशेषज्ञों, विद्वानों और कलाकारों की यात्राएं आयोजित की हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से, भारत की सबसे पुरानी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के थिंक टैंक, भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने एससीओ निवासी शोधकर्ता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में एससीओ सदस्य देशों के युवा विद्वानों को एक महीने की अवधि के लिए होस्ट करना शामिल था। इस अवधि के दौरान, विद्वानों ने भारत में विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और दिल्ली के साथ-साथ सोनीपत, बैंगलोर, चेन्नई और पुडुचेरी सहित अन्य भारतीय शहरों में अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों का दौरा किया।

यह खंड आईसीडब्ल्यूए में एससीओ निवासी शोधकर्ता कार्यक्रम के युवा प्रतिभागियों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए शोध का एक संग्रह है। ये शोध संगठन की प्रगति, इसके भविष्य के विकास, चुनौतियों और भावी राह पर विद्वानों के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कजाखस्तान के गुलडेन कास्करबायेवा ने एससीओ को 'आधुनिक दुनिया का मॉडल' करार दिया है, जहां लगभग सभी धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। वह आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद द्वारा उत्पन्न सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती से निपटने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नोट करती है। चीन एससीओ के सदस्य देशों के बीच सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की वर्तमान स्थिति की जांच करता है और इसे और सुदृढ़ करने का आग्रह करता है। किर्गिस्तान के बातिर कारागुलोव एससीओ के सदस्य देशों के साझा भविष्य के लिए तर्क देते हैं और विविधता को अपनाने और नए उत्साह के साथ साझा आधार की खोज करने का दावा करते हैं। वह बैंकिंग और सीमा शुल्क संघ के गठन के माध्यम से अधिक आर्थिक सहयोग पर जोर देता है। रूस के डॉ. दिमित्री नोविकोव एससीओ पर चल रहे भू-राजनीतिक दरारों के प्रभाव की जांच करते हैं और एससीओ को ग्रेटर यूरेशिया की

संस्थागत रीढ़ के रूप में स्थापित करने का मामला बनाते हैं। ताजिकिस्तान के फरीदुन रहीमोव ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे की जांच की और तर्क दिया कि एससीओ अपनी सामूहिक क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इस चुनौती का सामना करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। उजबेकिस्तान के कामरोनबेक दावलातोव ने एससीओ में सुदृढ़ संयोजकता का आह्वान किया और तर्क दिया कि आईएनएसटीसी और चाबहार बंदरगाह जैसी पहल क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा

देगी।

यह प्रकाशन एससीओ की भूमिका और भविष्य के बारे में एससीओ सदस्य देशों के युवा शोधकर्ता समुदाय के बीच प्रचलित सोच में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान प्रकाशन राजनयिक चिकित्सकों के साथ-साथ एससीओ की गतिविधियों में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

राजदूत विजय ठाकुर सिंह

महानिदेशक

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

जून 2023

सुश्री गुल्डेन कास्करबायेवा

विशेषज्ञ, विदेश नीति अनुसंधान संस्थान,
पीएच.डी. छात्र, एल.एन. गुमिलोव यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी,
अस्ताना, कजाकिस्तान

श्री ज़ौ झेंगशिन

दक्षिण एशिया-पश्चिम चीन सहयोग और विकास अध्ययन केंद्र, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिचुआन विश्वविद्यालय में निदेशक सहायक और राजनीति विज्ञान में पीएच.डी. विद्वान, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत।

श्री कारागुलोव बटीर-मुखम्मद आज़मतोविच

किर्गिज़ गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी विभाग में विशेषज्ञ

डॉ. दिमित्री पावलोविच नोविकोव

उप प्रमुख, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉस्को, और अग्रणी शोधकर्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना एंड कंटेम्परारी एशिया, रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज, मॉस्को

श्री रहीमोव फरीदुन

जूनियर रिसर्च फेलो, यूरोप और अमेरिका विभाग, आईएसपीएईसी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, ताजिकिस्तान, दुशांबे

श्री दावलातोव कामरोनबेक संजरबेक उगली

शोधकर्ता, उजबेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के तहत विश्व अर्थव्यवस्था और कूटनीति विश्वविद्यालय, ताशकंद

भारतीय वैश्विक परिषद

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एससीओ की भूमिका

गुलडेन कास्करबायेवा

शंघाई सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण एशियाई राजनीतिक मंच का दर्जा प्राप्त करता है, जिसकी गतिविधियां मुख्य रूप से क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने पर केंद्रित हैं, और सीआईएस देशों, मध्य पूर्व, दक्षिण और पूर्व एशिया के बीच सहयोग विकसित करने के हितों में मांग में एक संवाद मंच बन रही हैं। इस प्रकार, वर्तमान में, एससीओ में 8 सदस्य राष्ट्र, 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र और 9 संवाद भागीदार राष्ट्र शामिल हैं।

चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा 2001 में हस्ताक्षरित एससीओ की स्थापना पर घोषणा, विशाल यूरो-एशियाई क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रणाली की नींव रखने का एक प्रयास था। यह आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई सहित क्षेत्रीय और विश्व सुरक्षा के मुद्दे थे, जो 21वीं सदी की शुरुआत में नए अंतरराष्ट्रीय संगठन के एजेंडे पर हावी थे।

आज, एससीओ के सदस्य देश यूरेशिया के 60 प्रतिशत क्षेत्र को एकजुट करते हैं, जहां 3.4 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का 41 प्रतिशत से अधिक है। संगठन में ऐसे देश शामिल हैं जो व्यापक और आत्मनिर्भर कच्चे माल, श्रम और बौद्धिक संसाधनों की उपस्थिति के कारण एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (38.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) का लगभग 30 प्रतिशत, विश्व व्यापार (5.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) का 16 प्रतिशत से अधिक है। वहीं, 2021 में आपसी व्यापार लगभग 768 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 'आधुनिक दुनिया के मॉडल' के रूप में एससीओ की भूमिका पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, जहां लगभग सभी विश्व धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भू-राजनीतिक अशांति के संदर्भ में, एससीओ के संरचना के भीतर बनाए गए संचार चैनल सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में संतुलित सहयोग बनाने और वास्तव में यूरेशियन महाद्वीप के देशों के विकास के लिए वैक्टर निर्धारित करना संभव बनाते हैं।

वर्तमान चरण में, एससीओ ने विकास की एक जटिल और अनिश्चित अवधि में प्रवेश किया है, जो गतिशील रूप से बदलते और संघर्ष पैदा करने वाले भू-राजनीतिक वातावरण की विशेषता है। इस प्रकार, शंघाई सहयोग संगठन (15-16 सितंबर, 2022, समरकंद) के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 22वीं बैठक भू-राजनीतिक स्थिति की अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में आयोजित की गई थी। शिखर सम्मेलन के आसपास की राजनीतिक पृष्ठभूमि यूक्रेन में रूसी युद्ध, ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिति में वृद्धि, अफगानिस्तान में गहराते संकट, किर्गिज-ताजिक और अफगान-पाकिस्तानी सीमाओं पर संघर्ष, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सैन्य संघर्ष से ढकी हुई थी।

> 'आधुनिक दुनिया के मॉडल' के रूप में एससीओ की भूमिका पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, जहां लगभग सभी विश्व धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

इस बीच, एससीओ समग्र क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। नाटो से स्वतंत्र एक सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण और एक बहुध्रुवीय दुनिया के नए केंद्रों के गठन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख देशों-रूस और चीन की भागीदारी-एससीओ में नए भागीदारों को आकर्षित करती है। संगठन ने यूरेशिया के विशाल क्षेत्र को कवर किया है, जिससे भूगोल इसका रणनीतिक लाभ बन गया है। वर्तमान में, महाद्वीप पर कोई समान संरचना नहीं है जो सीआईएस, मध्य पूर्व, दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक नियमित उच्च स्तरीय वार्ता सुनिश्चित करेगी।

अपने अस्तित्व के वर्षों में, एससीओ ने सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसमें आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खतरों के खिलाफ संयुक्त लड़ाई शामिल है। विशेष रूप से, रक्षा मंत्रियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक प्राधिकरणों के प्रमुखों, सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठकों के लिए तंत्र बनाए गए थे, जिसके भीतर परामर्श आयोजित किए जाते हैं और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई समन्वित की जाती है।

इस स्तर पर, राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने, आपसी विश्वास, समान और खुले संवाद पर आधारित 'शंघाई भावना' को और सुदृढ़ करना बेहद महत्वपूर्ण है। एससीओ मंच पर बहुपक्षीय बैठकों का प्रारूप घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना, कुछ क्षेत्रीय तनावों को दूर करना, क्षेत्र में मनोदशा, संगठन के सदस्यों और भागीदारों की आकांक्षाओं को महसूस करना और उनकी पहल के लिए समर्थन जुटाना संभव बनाता है।

> अपने अस्तित्व के वर्षों में, एससीओ ने सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसमें आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खतरों के खिलाफ संयुक्त लड़ाई शामिल है।

इसलिए समरकंद शिखर सम्मेलन ने महामारी के बाद पहली बार इकट्ठे नेताओं को संचित मुद्दों पर 'सिंक्रनाइज़ करने' का अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव की वर्तमान स्थितियों में। वैश्विक संकट की पृष्ठभूमि में, उन्होंने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठन की महान क्षमता और समस्याओं को हल करने में क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि व्यापार और आर्थिक संबंधों के लिए एक स्थिर तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया। समरकंद में शिखर सम्मेलन में औद्योगिक सहयोग, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटलीकरण और व्यापार सहित सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 44 दस्तावेजों को अपनाया गया। एससीओ सदस्य देशों के दीर्घकालिक अच्छे पड़ोसी, मित्रता और सहयोग पर संधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2023-2027 के लिए एक व्यापक कार्य योजना भी अपनाई गई थी। समरकंद शिखर सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि एससीओ के सदस्य राष्ट्र, अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार और आम सहमति के आधार पर, आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एक सूची

बनाने के लिए सामान्य सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे, जिनकी गतिविधियां एससीओ सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्रों पर निषिद्ध हैं।

प्रतिभूति

पिछले शिखर सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला में, अफगानिस्तान में संकट की स्थिति, आतंकवाद, कट्टरपंथ और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लड़ाई, परिवहन और रसद गलियारों और पारगमन के अवसरों के संयुक्त विकास और उपयोग, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ऊर्जा चर्चा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया जैसे सामयिक मुद्दों को शामिल किया गया था। एससीओ के सदस्यों ने आतंकवाद, युद्धों और नशीली दवाओं से मुक्त एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकीकृत, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान की स्थापना की वकालत की, और इसे 'समावेशी सरकार' के गठन को 'अत्यंत महत्वपूर्ण' कहा, जिसमें अफगान समाज में सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हों। इस प्रकार, संगठन की क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, 'तीन बुराइयों की ताकतों'-आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के कारणों, स्रोतों और अभिव्यक्तियों के उन्मूलन को प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह एससीओ के हाशिए पर था कि एक दस्तावेज अपनाया गया था-आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने पर शंघाई कन्वेंशन, 15 जून, 2001, जिसने 'आतंकवाद' की अवधारणा को परिभाषित किया। सुरक्षा के क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग हमेशा एक प्रमुख कार्य के रूप में संगठन के एजेंडे पर होता है, जो बदले में पूरे क्षेत्र के स्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास का गारंटर होता है।

इस दिशा में, महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) को सौंपी गई है-एससीओ का एक स्थायी निकाय, जो 'तीन बुराइयों'-आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खतरों के खिलाफ लड़ाई में लगातार काम कर रहा है। एससीओ सदस्य देशों की आतंकवाद विरोधी क्षमता को बढ़ाने के व्यावहारिक तरीकों में से एक 2006 के बाद से वार्षिक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित करना है, जिसके दौरान विभिन्न आतंकवादी खतरों और आतंक के कृत्यों को बेअसर करने के लिए सक्षम अधिकारियों के बीच प्रतिक्रिया तंत्र और चर्चा का व्यावहारिक विकास किया जाता है।

अवैध प्रवास, नशीली दवाओं, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी सहित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों से एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण, एससीओ सदस्यों के सक्षम अधिकारियों की सीमा सेवाओं के बीच चर्चा के लिए आरएटीएस तंत्र है। 2013 के बाद से, एससीओ सदस्य देशों की सीमाओं पर आठ संयुक्त सीमा अभियान चलाए गए हैं। आतंकवादी और प्रचार उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के उपयोग को रोकने के लिए किए जा रहे लगातार उपाय, एससीओ आतंकवाद विरोधी संरचनाओं

की कर्मियों की क्षमता बढ़ाने और उनके संपर्कों को बनाए रखने के लिए आरएटीएस के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यावहारिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए, क्षेत्र में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है।

एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए तंत्र में सुधार करने के लिए, आरएटीएस के आधार पर एससीओ सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए सार्वभौमिक केंद्र, एससीओ सूचना सुरक्षा केंद्र बनाने के लिए एससीओ पहलों को लागू करना महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम, साथ ही एंटी-ड्रग सेंटर एक अलग स्थायी निकाय के रूप में।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरएटीएस, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने के लिए संगठन के समन्वय केंद्र के रूप में, एससीओ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशेष रूप से, एससीओ की सुरक्षा के लिए पारंपरिक और नए प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए निवारक उपायों के अनुप्रयोग, साथ ही सामाजिक-आर्थिक कारणों को खत्म करने के लिए कदम जो आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के लिए जमीन बनाते हैं, क्षेत्र में स्थिरता और सतत विकास को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

अर्थव्यवस्था

सुरक्षा खतरों और चुनौतियों के नए स्रोतों के उद्भव का मुकाबला करने के संदर्भ में आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास में निरंतर असमानता तेजी से कट्टरता का कारण है। इस संदर्भ में, एससीओ विश्व अर्थव्यवस्था की बहाली को गति देने, पारदर्शिता, पारस्परिक सम्मान, समानता के सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विकास की वकालत करता है, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता को संरक्षित करने और बनाए रखने के हितों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देगा।

वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के मुक्त आवागमन के लिए क्रमिक संक्रमण के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच विभिन्न रूपों में आर्थिक सहयोग का विकास महत्वपूर्ण है। इस संबंध में पारगमन और परिवहन क्षेत्र, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा में एससीओ के संरचना के भीतर बड़े पैमाने पर आर्थिक परियोजनाओं को लागू करना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, एससीओ देशों ने कई दस्तावेजों को अपनाया, जिनमें 2023-2025 के लिए अंतर-क्षेत्रीय व्यापार विकास पर योजना, संयोजकता विकसित करने और कुशल आर्थिक और परिवहन गलियारों के निर्माण में एससीओ सदस्य देशों के सहयोग की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए एससीओ सदस्य राष्ट्रों का समझौता, पारस्परिक निपटान में राष्ट्रीय मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एससीओ सदस्य देशों का रोडमैप, पर्यटन सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौता शामिल है। वहीं आर्थिक सहयोग के विकास के लिए समरकंद शिखर सम्मेलन में रोजगार और समृद्धि बढ़ाने के लिए डिजिटल

साक्षरता को बढ़ावा देने और ई-कॉमर्स क्षेत्र के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ये कदम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विकास, व्यापार, निवेश, बुनियादी संरचना के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के साथ-साथ आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान करते हैं।

संस्कृति

संगठन के सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्र है। एससीओ के संरचना के भीतर स्थापित विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का स्थिर संवाद सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी को और सुदृढ़ करने और देशों और लोगों के तालमेल में योगदान देता है।

इस संबंध में, एससीओ के संरचना के भीतर सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग का प्रगतिशील विकास, लोगों के बीच आपसी समझ को सुदृढ़ करना, सदस्य देशों की सांस्कृतिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए सम्मान, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, त्योहारों और प्रतियोगिताओं का आयोजन, देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग की तीव्रता, और साथ ही, क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का अध्ययन और संरक्षण एससीओ के व्यावहारिक कार्य की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

> संगठन में भारत का प्रवेश, इसकी विशाल आर्थिक क्षमता और शांतिपूर्ण विदेश नीति के साथ निस्संदेह एससीओ को सुदृढ़ करता है।

समरकंद में शिखर सम्मेलन में, एससीओ सदस्य देशों के नेताओं ने 2023 को पर्यटन वर्ष घोषित करने का निर्णय किया, साथ ही भारतीय शहर वाराणसी को 2022-2023 के लिए संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया। ये कदम लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को और लोकप्रिय बनाने और एससीओ सदस्य देशों की पर्यटन क्षमता के विकास में योगदान देंगे।

भारत और एससीओ

संगठन में भारत का प्रवेश, इसकी विशाल आर्थिक क्षमता और शांतिपूर्ण विदेश नीति के साथ निस्संदेह एससीओ को सुदृढ़ करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) सहित दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक व्यापार और पारगमन प्रणाली स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, चाबहार के ईरानी बंदरगाह का व्यापक उपयोग, जिसे भारत द्वारा विकसित

किया जा रहा है, और 2023 में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करना, एससीओ अंतरिक्ष में अंतर-क्षेत्रीय संचार की संभावनाओं का विस्तार करता है, और संगठन की पारगमन क्षमता के विकास में भी योगदान देता है।

एससीओ सदस्य देशों के साथ अनुभव साझा करने के लिए स्टार्टअप और नवाचार पर एक नया टास्क फोर्स बनाने की भारत की पहल, साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ कार्य समूह, आम लोगों के लिए व्यावहारिक लाभ के साथ एससीओ अंतरिक्ष में आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने में मदद करेगा।

कजाकिस्तान और एससीओ

संगठन की स्थापना के बाद से, कजाकिस्तान गणराज्य सक्रिय संस्थापक राष्ट्रों में से एक रहा है, जिसने कई अलग-अलग विचारों, परियोजनाओं, दस्तावेजों और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। विशेष रूप से, कजाख पक्ष के सुझाव पर, सीमा मुद्दों पर एससीओ सदस्य देशों के सहयोग और चर्चा पर समझौते पर हस्ताक्षर, 2025 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाने, आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम एससीओ, जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई है। 2019-2020 में एंटी-ड्रग ऑपरेशन पॉटीना (वेब), और अन्य।

> एससीओ सदस्य देशों के साथ अनुभव साझा करने के लिए स्टार्टअप और नवाचार पर एक नया टास्क फोर्स बनाने की भारत की पहल, साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ कार्य समूह, आम लोगों के लिए व्यावहारिक लाभ के साथ एससीओ अंतरिक्ष में आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने में मदद करेगा।

कजाकिस्तान एससीओ के महत्वपूर्ण निकायों में से एक का आरंभकर्ता भी है-सरकार के प्रमुखों की परिषद, जो व्यावहारिक क्षेत्रों में चर्चा विकसित करने के मौलिक मुद्दों को हल करती है, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में। 2006 से, एससीओ सचिवालय के लिए कजाकिस्तान गणराज्य का स्थायी मिशन बीजिंग में काम कर रहा है। एससीओ के संरचना के भीतर चर्चा कजाकिस्तान गणराज्य की विदेश नीति की महत्वपूर्ण दिशाओं में से एक है। एससीओ भागीदार देशों के साथ रचनात्मक भागीदारी और समान चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना इस क्षेत्र में कजाकिस्तान की स्थिति को सुदृढ़ करता है, राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास और समझ के विकास में योगदान देता है। एससीओ के संरचना के भीतर कजाकिस्तान गणराज्य की मुख्य प्राथमिकताएं क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक साझेदारी विकसित करना, पारगमन और परिवहन क्षमता को अनलॉक करना, साथ ही सांस्कृतिक और मानवीय बंधन को गहरा करना है। शंघाई प्रक्रिया की शुरुआत से ही, कजाकिस्तान एससीओ प्रारूप के भीतर बहुपक्षीय सहयोग में एक सक्रिय भागीदार रहा है, जिसने अपने कानूनी संरचना को सुदृढ़ करने में एक महान योगदान दिया है।

> एससीओ के संरचना के भीतर कजाकिस्तान गणराज्य की मुख्य प्राथमिकताएं क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक साझेदारी विकसित करना, पारगमन और परिवहन क्षमता को अनलॉक करना, साथ ही सांस्कृतिक और मानवीय बंधन को गहरा करना है।

कजाकिस्तान ने 2010-2011 और 2016-2017 में एससीओ की अध्यक्षता की। प्रत्येक अवधि की अपनी विशेषताएं थीं और महत्वपूर्ण निर्णयों को अपनाने से चिह्नित किया गया था जिसने एससीओ में क्षेत्रीय सहयोग के विकास को अतिरिक्त गति दी थी। विशेष रूप से, 2017 में अस्ताना एससीओ शिखर सम्मेलन एसोसिएशन के विकास में एक नया अध्याय बन गया। एससीओ के इतिहास में पहली बार दो नए राष्ट्रों- भारत और पाकिस्तान के पूर्ण सदस्यों के प्रवेश के माध्यम से संगठन की सदस्यता का विस्तार हुआ। निस्संदेह, एससीओ में नए सदस्यों का प्रवेश खुलेपन के सिद्धांतों और संवाद विकसित करने की इच्छा के प्रति एससीओ के संस्थापक राष्ट्रों के सामान्य दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जैसा कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना पर 2001 की घोषणा में परिलक्षित होता है। इसके साथ ही राष्ट्राध्यक्षों ने चरमपंथ का मुकाबला करने पर एससीओ कन्वेंशन को अपनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कट्टरपंथी आंदोलनों को बेअसर करना, संभावित विनाशकारी ताकतों की पहचान करना और विभिन्न चरमपंथी विचारों के प्रचार का तुरंत कार्रवाई करना है।

समरकंद एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने, इस क्षेत्र में पहले से अपनाए गए दस्तावेजों के कार्यान्वयन को जारी रखने और संगठन के सूचना स्थान की रक्षा के लिए बुनियादी संरचना का निर्माण करने और एससीओ और मध्य एशियाई क्षेत्रीय सूचना समन्वय केंद्र के बीच चर्चा को सुदृढ़ करने के लिए साइबर अपराध का मुकाबला करने और रक्षा विभागों और विशेष सेवाओं के बीच सैन्य-राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग का निर्माण करने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही, संगठन की मौजूदा विशाल मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, पारगमन और परिवहन क्षेत्र, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित एससीओ के संरचना के भीतर आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार, क्षेत्र के देशों के परस्पर संबंध सुनिश्चित करने

के उद्देश्य से आशाजनक परियोजनाओं का कार्यान्वयन, मध्य और दक्षिण एशिया के बीच परिवहन मार्गों का विस्तार करने के प्रयास, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम ट्रांस-यूरेशियन गलियारों का विकास, नए का निर्माण और मौजूदा मल्टीमॉडल परिवहन गलियारों का आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

'तीन बुराइयों' के खिलाफ लड़ाई, राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने जैसे प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित एससीओ की गतिविधियों का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्थिरता बनाए रखना, संयुक्त रूप से नई चुनौतियों और खतरों का सामना करना, क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को सुदृढ़ करना है। इस तथ्य के कारण कि आधुनिक दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के गंभीर उत्तेजना के दौर में प्रवेश किया है, एससीओ के काम के ऐसे क्षेत्र: एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी को सुदृढ़ करना; क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और सुदृढ़ करने के लिए बहु-विषयक सहयोग का विकास; आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के सभी अभिव्यक्तियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई; अवैध नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी का मुकाबला करना, अन्य प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि, साथ ही अवैध प्रवास, अतिरिक्त महत्व प्राप्त करते हैं।

भारतीय वैश्विक परिषद

एससीओ राष्ट्रध्यक्ष परिषद - 2023

S | E | C | U | R | E | SCO

शंघाई सहयोग संगठन सूचना सुरक्षा सहयोग

वर्तमान स्थिति और नीति विकल्प

ज़ौ झेंगशिन

इसकी स्थापना के बाद से, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का मूल और प्रोत्साहन सुरक्षा सहयोग है। साइबर अपराध का मुकाबला करना और अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा को बनाए रखना ऐसे मुद्दे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ सामना करने की आवश्यकता है, और वे एससीओ सुरक्षा सहयोग के लिए नई चुनौतियां और नए विषय भी हैं। एससीओ सूचना सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बहुत महत्व देता है, और चीन, रूस और भारत जैसे सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए सूचना सुरक्षा के विशेष महत्व को पूरी तरह से पहचानते हैं, और सूचना सुरक्षा सहयोग के स्तर में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एससीओ ने सूचना सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया

एससीओ का सूचना सुरक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास है, और 2001 में इसकी स्थापना के बाद से, 10 से अधिक दस्तावेज सूचना सुरक्षा सहयोग के विषय के लिए समर्पित हैं। 2005 में पांचवें एससीओ शिखर सम्मेलन में, आधिकारिक दस्तावेज में सूचना आतंकवाद का पहली बार उल्लेख किया गया था। 2006 के शंघाई शिखर सम्मेलन में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों का बयान, एक मार्गदर्शक दस्तावेज है और सूचना सुरक्षा में एससीओ सहयोग के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला है[1]। वक्तव्य में अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर एससीओ सदस्य देशों के विशेषज्ञों का एक समूह स्थापित करने के इरादे का भी उल्लेख किया गया है[1]। तब से, लगभग सभी शिखर सम्मेलनों ने एससीओ सूचना सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की है, और इसके अर्थ और विस्तार समृद्ध और अधिक विशिष्ट हो गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सहयोग के लिए खतरे, इंटरनेट सुरक्षा के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के संप्रभु अधिकार की गारंटी कैसे दी जाए, डिजिटलीकरण और सूचना के क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे सतर्क रहें और आईसीटी को आतंकवादियों द्वारा उपयोग करने से रोका जाए। अलगाववादी और चरमपंथी संगठन, आदि।

> एससीओ का सूचना सुरक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास है, और 2001 में इसकी स्थापना के बाद से, 10 से अधिक दस्तावेज सूचना सुरक्षा सहयोग के विषय के लिए समर्पित हैं।

> एससीओ की अध्यक्षता के रूप में, भारत का 2023 का विषय "एक सुरक्षित एससीओ की ओर" है, सूचना सुरक्षा भी तैयार है। भारत ने एससीओ सदस्य देशों के साथ साइबर सुरक्षा या सूचना सुरक्षा पर कई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किए हैं।

2021 में, एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर, सदस्य देश दुशांबे में एकत्र हुए और 2022-2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की योजना तैयार की, और एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर दुशांबे घोषणा जारी की[2]। दुशांबे घोषणा, अपने सुरक्षा अध्याय में, सूचना सुरक्षा के महत्व पर व्यापक रूप से जोर देती है, एससीओ क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा की गारंटी को प्राथमिकता का कार्य बनाती है, संचार प्रौद्योगिकियों के विकास में बाधा डालने वाली किसी भी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का विरोध करती है, शांति और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का समर्थन करती है और सक्रिय रूप से शांति और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देता है। समरकंद शहर में राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 16 सितंबर 2022 की बैठक में, सदस्य राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग के महत्व की पुष्टि की और एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के आधार पर एससीओ सूचना सुरक्षा केंद्र (कजाकिस्तान गणराज्य) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। एससीओ की अध्यक्षता के रूप में, भारत का 2023 का विषय "एक सुरक्षित एससीओ की ओर" है, सूचना सुरक्षा भी तैयार है। भारत ने एससीओ सदस्य देशों के साथ साइबर सुरक्षा या सूचना सुरक्षा पर कई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किए हैं। 14-15 दिसंबर 2022 को, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), भारत सरकार ने एक ज्ञान भागीदार के रूप में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के सहयोग से एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए "साइबरस्पेस फ्रंटियर्स की सुरक्षा" पर दो दिवसीय व्यावहारिक संगोष्ठी का आयोजन किया। चर्चा का केंद्र इस बात पर था कि कैसे सोशल मीडिया अपनी धमकियों और चुनौतियों के साथ आतंकवादियों के "टूलकिट" में बदल रहा है[3]।

मुख्य विकास और चुनौतियां

एससीओ ने पिछले दो दशकों में सूचना सुरक्षा सहयोग में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें आरएटीएस की स्थापना और सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर एससीओ विशेषज्ञ समूह का गठन, 'साइबर-आतंकवाद' का मुकाबला करने पर अभ्यास का संचालन और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना शामिल है।

आरएटीएस की स्थापना: एससीओ के अस्तित्व के दूसरे वर्ष में, 7 जून, 2002 को सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक के दौरान एससीओ के स्थायी निकाय के रूप में नामित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की स्थापना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे[4]। अपनी स्थापना के बाद से, एससीओ आरएटीएस ने संगठन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और क्षेत्रीय, वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने के लिए संगठन के प्रयासों का स्तंभ और केंद्र बिंदु बन गया है। एससीओ आरएटीएस के आंकड़ों के अनुसार, 2013 और 2019 के बीच, एससीओ ने 960 से अधिक आतंकवादी-संबंधित आपराधिक गतिविधियों को कुचल दिया और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के 2,600 से अधिक सदस्यों से संपर्क किया[5]। आरएटीएस परिषद की 38वीं बैठक 14 अक्तूबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में भारत,

कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आरएटीएस एससीओ की कार्यकारी समिति के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। बैठक में कार्यकारी समिति की कार्य योजना के साथ-साथ सीमा रक्षा और साइबर-आतंकवाद में विशेष सहयोग कार्यक्रमों को अपनाया गया और क्षेत्रों से आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए 2023 में संयुक्त सीमा अभियान जारी रखने का निर्णय लिया गया। पार्टियों ने कार्यकारी समिति के संगठन, कर्मियों और वित्त के साथ-साथ 'तीन बुराइयों' (आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद) का मुकाबला करने के क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों के कानूनी आधार को बढ़ाने के बारे में प्रस्तावों की एक श्रृंखला को अपनाया[6]।

अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर एससीओ विशेषज्ञ समूह का गठन: अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर विशेषज्ञ समूह एससीओ का एक स्थायी निकाय है। 2006 से, यह प्रासंगिक मंत्रालयों और विभागों के समन्वय का प्रभारी रहा है, दो स्थायी एससीओ निकायों, अर्थात् सचिवालय और एससीओ आरएटीएस की कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ विशेषज्ञ समूह की बैठकें आयोजित करता है। विशेषज्ञ समूह का प्राथमिक कार्य इस क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों के कानून, सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा और संभावित खतरों के साथ-साथ उनका मुकाबला करने के लिए उचित साधनों और तरीकों को नियोजित करने की संभावनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना है, और खतरे की निगरानी और कार्यों के समन्वय के लिए व्यावहारिक तंत्र की स्थापना पर प्रासंगिक सिफारिशें करना है[7]।

अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा की सुरक्षा के लिए योजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने और विचार करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करके, विशेषज्ञ समूह सूचना सुरक्षा पर एक अंतर-सरकारी समझौते के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में एससीओ की शासन क्षमताओं, नीतियों और नियमों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

'साइबर-आतंकवाद' का मुकाबला करने पर अभ्यास आयोजित करना: वास्तविक सुरक्षा खतरों को रोकने और मुकाबला करने पर कानूनी दस्तावेजों की एक श्रृंखला को लागू करने के लिए, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन और चरमपंथ का मुकाबला करने पर एससीओ कन्वेंशन, एससीओ सदस्य राष्ट्रों ने 2015 के बाद से कई साइबर आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किए हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने, संभालने और मुकाबला करने में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सक्षम अधिकारियों के कानूनों और विनियमों, परिचालन प्रक्रियाओं, तकनीकी साधनों और कानून प्रवर्तन क्षमताओं का परीक्षण करना है, जो साइबर खतरों को रोकने और क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नवीनतम साइबर आतंकवाद विरोधी अभ्यास दिसंबर 2019 में फुजियान प्रांत के ज़ियामेन में आयोजित किया गया था, जिसमें आठ एससीओ सदस्य राष्ट्रों के सक्षम अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अभ्यास मानता है कि एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इंटरनेट पर आतंकवादी जानकारी प्रकाशित करता है और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास करता है, और एससीओ सदस्य

देशों द्वारा ऑनलाइन जानकारी की जांच और अनुसंधान का समन्वय करने, आतंकवाद में शामिल लोगों का पता लगाने और उनका अनुसरण आतंकवादी संगठन की संरचना की पहचान करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित करता है। वित्त पोषण के स्रोत, सदस्यों की भर्ती, और गुप्त शाखाएं, और संबंधित उपाय करना।

> अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा की सुरक्षा के लिए योजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने और विचार करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करके, विशेषज्ञ समूह सूचना सुरक्षा पर एक अंतर-सरकारी समझौते के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में एससीओ की शासन क्षमताओं, नीतियों और नियमों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

संयुक्त राष्ट्र के साथ चर्चा: एससीओ ने अपने अस्तित्व की शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र के साथ अच्छी चर्चा करता रहा है। सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में एससीओ और संयुक्त राष्ट्र एक-दूसरे का समर्थन और सहयोग करते हैं। एससीओ अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका को अत्यधिक मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों के संयुक्त वक्तव्य को 2020 में अपनाया गया था और इस बात की पुष्टि की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा का रखरखाव, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग, और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, खुला और स्थिर वैश्विक सूचना स्थान स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित। संयुक्त राष्ट्र ने भी एससीओ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। 25 मार्च 2021 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र ने अपनी 58वीं बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन के बीच सर्वसम्मति से संकल्प 75/69 सहयोग को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र ने भी एससीओ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। 25 मार्च 2021 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र ने अपनी 58वीं बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन के बीच सर्वसम्मति से संकल्प 75/69 सहयोग को अपनाया। प्रस्ताव शांति और सुरक्षा हासिल करने में एससीओ की रचनात्मक भूमिका को स्वीकार करता है और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक-आतंकवाद विरोधी रणनीति लागू करने में एससीओ आरएटीएस और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी केंद्र सहित संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय के बीच रचनात्मक सहयोग के साथ-साथ एससीओ आरएटीएस और आतंकवाद विरोधी समिति कार्यकारी निदेशालय के बीच 25 मार्च 2019 दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग का संज्ञान लेता है।[8]

यूरोप और एशिया में फैले एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, जो वैश्विक आबादी के लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत को कवर करता है और 8 सदस्य देशों, 4 पर्यवेक्षक देशों और 9 संवाद भागीदार देशों के साथ, इसका सूचना सुरक्षा सहयोग अभी भी आदर्श से बहुत दूर है। सबसे पहले, सूचना सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का कार्यान्वयन लागू नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है, हाल के वर्षों में एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट चीफ ने निश्चित रूप से सूचना सुरक्षा का उल्लेख किया है, और सूचना सुरक्षा सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, लेकिन अधिक कागज पर

परिलक्षित होता है और लागू नहीं किया जाता है, और कोई विशिष्ट कार्यान्वयन रणनीति पेश नहीं की गई है, जो आम तौर पर सामग्री की तुलना में अधिक रूप है और कार्रवाई की तुलना में अधिक बयानबाजी, जो सीधे संगठन की कार्यान्वयन दक्षता को प्रभावित करती है। प्रासंगिक तंत्र के संचालन में निरंतरता की कमी दूसरा मुद्दा है। एससीओ ने सूचना सुरक्षा सहयोग के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं; हालांकि, कोविड-19 के प्रकोप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ समूह की बैठकों को स्थगित कर दिया गया है, विशेष रूप से 2015 में लॉन्च बैठक के बाद से साइबर आतंकवाद विरोधी अभ्यास, 2015, 2017 और 2019 में चीन में केवल तीन बार आयोजित किया गया था, और फिर बाधित किया गया था। अध्यक्ष के रूप में भारत के पास अभी तक कोई खबर नहीं है कि साइबर आतंकवाद विरोधी अभ्यासों का एक नया दौर आयोजित किया जाएगा, और इस तंत्र में व्यवधान का खतरा है। तीसरा, सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों की भूमिका विषम है। सूचना शक्तियों के रूप में चीन और रूस इस क्षेत्र में "नायक" रहे हैं, जबकि अन्य मध्य एशियाई देशों ने इसमें अधिक सीमित भूमिका निभाई है।

उपर्युक्त समस्याओं का सुगम समाधान निकाला जा सकता और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की राष्ट्रीय स्थितियों और सूचना सुरक्षा की अनूठी प्रकृति से निकटता से संबंधित हैं। सबसे पहले, सूचना सुरक्षा की विशेष और संवेदनशील प्रकृति स्वयं प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के लिए एक एकीकृत सूचना मंच के निर्माण को सीमित करती है। एससीओ के भीतर सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों और सूचना सुरक्षा पर सहयोग ने साइबर संप्रभुता के मुद्दे के बारे में कुछ देशों की चिंता बढ़ा दी है[9]। दूसरा, साइबर प्रबंधन प्रणाली, साथ ही सदस्य देशों के कानून और नियम, अलग हैं। सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ समूह की बैठक को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, बैठक में चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आम तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्र इंटरनेट सूचना कार्यालय के सदस्यों के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि रूसी पक्ष का नेतृत्व संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) द्वारा किया जाता है[10]। साइबर प्रबंधन प्रणालियों में अंतर संस्थागत संरेखण की सुविधा नहीं देता है और सम्मेलन के परिणामों के कार्यान्वयन और निष्पादन में बाधा डालता है। तीसरा, सदस्य देशों के पास साइबर विकास के विभिन्न स्तर हैं और साइबर शासन के लिए अलग-अलग अपेक्षाएं हैं।

विशेष रूप से, चीन, रूस और भारत जैसी साइबर शक्तियां संगठित अपराधों और अन्य खतरों को संगठित करने के लिए सीमाओं के पार बहने के लिए आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को रोकने के लिए अधिक चिंतित हैं, जबकि साइबर प्रौद्योगिकी विकास में पिछड़ने वाले छोटे और मध्यम आकार के सदस्य राष्ट्र देश में आतंकवादी विचारों और गतिविधियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अधिक चिंतित हैं।

भावी राह

एससीओ की सूचना सुरक्षा कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जबकि आगे सहयोग के लिए भी बहुत गुंजाइश और संभावना है। पहला सदस्य देशों के बीच "डिजिटल विभाजन" को कम करना है। सदस्य देशों

के आर्थिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा शासन क्षमताओं के विभिन्न स्तरों के कारण, सूचना सुरक्षा जोखिमों के लिए उनका लचीलापन और उनसे निपटने की क्षमता काफी भिन्न होती है। इसलिए, जैसा कि एससीओ सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है, देशों को अधिक क्षेत्रीय सुरक्षा और समग्र विकास परिप्रेक्ष्य लेना चाहिए, भू-राजनीतिक पूर्वाग्रह और सूचना सुरक्षा की अंतर्निहित संवेदनशीलता को छोड़ना चाहिए, सूचना सुरक्षा सहयोग को गहरा करना जारी रखना चाहिए, सूचना सुरक्षा की तकनीकी सुरक्षा के स्तर में सुधार के लिए 5 जी और एआई जैसी नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना के निर्माण में सुधार, सूचना डेटा संरक्षण प्रणाली में सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी में अनुभव के आदान-प्रदान और पारस्परिक प्रशंसा को सुदृढ़ करना, कुशल और सुरक्षित सूचना विनिमय तंत्र के गठन को बढ़ावा देना, और संयुक्त रूप से व्यावहारिक प्रतिवाद विकसित करना[11]। साथ ही, देशों को साइबर शक्तियों के फायदों का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग योगदानों पर भी विचार करना चाहिए। इसकी तुलना में, चीन, रूस और भारत के पास कानूनी संरचना, तकनीकी उपकरण और परिचालन क्षमताओं आदि में सुदृढ़ फायदे हैं। संभावित सूचना सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हुए, तीनों देशों को एससीओ आम सहमति के आधार पर एक सुरक्षित, कुशल और सहयोगी सूचना सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए अधिक जिम्मेदारियों और दायित्वों को संभालने की आवश्यकता है।

दूसरा, क्षेत्रीय डिजिटल शासन को बढ़ावा देना और एक सूचना सुरक्षा समुदाय का निर्माण करना है। इसकी आवश्यकता है: प्रत्येक सदस्य देश को "नरम" और "कठिन" डिजिटल बुनियादी संरचना के निर्माण में तेजी लानी चाहिए, और प्रौद्योगिकी अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए; सरकार, उद्यमों और निजी क्षेत्र के सभी स्तरों पर संचार और समन्वय को सुदृढ़ करना, और प्रत्येक देश के डिजिटल प्लेटफार्मों और डिजिटल रणनीतियों के एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना; प्रत्येक देश को नियामक प्रणाली, डिजिटल नियमों, डेटा साझाकरण और डेटा सुरक्षा संरक्षण जैसे मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, ताकि एकीकृत एससीओ सूचना और डेटा प्लेटफॉर्म और सूचना सुरक्षा समुदाय के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सकें।

> एससीओ के सामने सबसे जरूरी कार्यों में से एक सूचना सुरक्षा सहयोग पर सदस्य देशों द्वारा बनी सहमति को वैध और संस्थागत बनाना और एक कुशल और पूर्ण सूचना सुरक्षा सहयोग तंत्र स्थापित करना है।

तीसरा, सूचना सुरक्षा के संस्थागत तंत्र में सुधार करना है। एससीओ के सामने सबसे जरूरी कार्यों में से एक सूचना सुरक्षा सहयोग पर सदस्य देशों द्वारा बनी सहमति को वैध और संस्थागत बनाना और एक कुशल और पूर्ण सूचना सुरक्षा सहयोग तंत्र स्थापित करना है। आदर्श रूप से, देशों को एक व्यापक और व्यवस्थित सूचना सुरक्षा सहयोग तंत्र बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए: सूचना सुरक्षा पर उच्च स्तरीय परामर्श के लिए एक तंत्र, एससीओ शिखर सम्मेलनों में अधिक सूचना सुरक्षा से संबंधित सामग्री को जोड़ना, और नियमित कार्यान्वयन समीक्षा; सूचना सुरक्षा प्रारंभिक चेतावनी तंत्र, सदस्य राष्ट्र नेटवर्क गतिशीलता की बारीकी से निगरानी करने के लिए अपने स्वयं के और एकीकृत प्लेटफार्मों का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, संभावित साइबर हमलों और जोखिम की घटनाओं पर अग्रिम चेतावनी प्रदान करते हैं और समय पर अधिसूचना और

उचित जोखिम नियंत्रण प्रदान करना; सूचना सुरक्षा आपातकालीन हैंडलिंग तंत्र, नेटवर्क सुरक्षा घटनाओं की घटना के बाद, संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाएं और आफ्टरकेयर प्रबंधन होना चाहिए; सूचना सुरक्षा अभ्यासों का तंत्र, अर्थात्, बाधित आतंकवाद विरोधी अभ्यासों का पुन: शुभारंभ, जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र में घूर्णन आधार पर आयोजित किए जाते हैं; और सूचना साझाकरण तंत्र, सदस्य देशों के बीच सूचना सुरक्षा और अनुभव साझा करने के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना, कर्मियों के एकीकृत प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।

अपनी स्थापना के बाद से पिछले 22 वर्षों में, एससीओ ने धीरे-धीरे अपने केंद्रीय बल और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि की है, सदस्य देशों के बीच राजनीतिक पारस्परिक विश्वास को सुदृढ़ किया है, सुरक्षा सहयोग को बनाए रखा है और गहरा किया है, आर्थिक सहयोग का बहुत विस्तार किया है, और क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में एक अद्वितीय योगदान देते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान का विस्तार किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ मिलकर, साइबर आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और सूचना हथियारों जैसे सुरक्षा खतरों की नई श्रेणियां उभरी हैं, जिन्होंने एससीओ सुरक्षा सहयोग के लिए नई आवश्यकताओं को सामने रखा है। एससीओ के सदस्य देशों ने सूचना सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन उनकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नए युग में एससीओ नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि अपने सदस्य राष्ट्रों के ठोस प्रयासों के माध्यम से यह क्षेत्रीय सूचना सुरक्षा को बनाए रखने में अधिक सफलता प्राप्त करेगा और वैश्विक बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा।

साझा जमीन की खोज, विविधता को अपनाना

एससीओ देशों का सामान्य भविष्य

कारागुलोव बटीर मुकम्मद आज़मतोविच

एससीओ देशों का साझा भविष्य कई चर्चाओं का विषय है, और बहुत आशा इस धारणा पर टिकी हुई है कि चर्चा और सहयोग क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। एससीओ की परिभाषित विशेषताओं में से एक इसके सदस्य राष्ट्रों की विविधता है, जो एक चुनौती और अवसर दोनों है। एक तरफ, विविधता गलतफहमी, संघर्ष और संसाधनों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा का कारण बन सकती है। दूसरी ओर, विविधता रचनात्मकता, नवाचार और पारस्परिक शिक्षा को भी जन्म दे सकती है, अगर देश सामान्य आधार खोजने और एक-दूसरे के मतभेदों का सम्मान करने में सक्षम हैं। एससीओ देशों के लिए एक समान भविष्य बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि वे अपने मतभेदों को दूर करने के तरीके खोजें और अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें।

इस सामान्य भविष्य को प्राप्त करने का एक तरीका आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना है। एससीओ देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों, मानव प्रतिभा और आर्थिक क्षमता का खजाना है, लेकिन वे गरीबी, असमानता, पर्यावरण क्षरण और बुनियादी संरचना के अंतराल जैसी आम चुनौतियों का भी सामना करते हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए मिलकर काम करके, एससीओ देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं की पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एससीओ देश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि सीमा पार राजमार्गों, पुलों और पाइपलाइनों का निर्माण, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने और वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए। वे टैरिफ को कम करके, गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके और व्यापार के लिए कानूनी और नियामक वातावरण में सुधार करके व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आर्थिक निर्भरता बढ़ाकर, एससीओ देश वृद्धि और विकास के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं, और संघर्ष और अस्थिरता के जोखिम को कम कर सकते हैं।

एससीओ देशों के लिए एक आम भविष्य प्राप्त करने का एक और तरीका सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एक-दूसरे की संस्कृतियों, इतिहास और मूल्यों के बारे में सीखकर, एससीओ देश एक-दूसरे की अपनी समझ और प्रशंसा को गहरा कर सकते हैं। यह विश्वास बनाने और सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान नेताओं और नागरिकों की एक नई पीढ़ी बनाने में भी मदद कर सकते हैं जो अधिक खुले दिमाग वाले, सहिष्णु और महानगरीय हैं, और जो 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए बेहतर सुसज्जित हैं। चर्चा और सहयोग के माध्यम से, एससीओ देश अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं और समृद्धि और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देकर, और सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर, एससीओ देश अपने लिए और दुनिया के लिए एक उज्जवल और अधिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

> एससीओ देशों के लिए एक समान भविष्य बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि वे अपने मतभेदों को दूर करने के तरीके खोजें और अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें।

एससीओ देश विभिन्न सुरक्षा खतरों के अधीन एक संवेदनशील भू-राजनीतिक क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र में कई आतंकवादी संगठन, चरमपंथी समूह और अलगाववादी आंदोलन काम करते हैं। ये समूह क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि एससीओ देश मिलकर इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करें। संयुक्त कार्रवाई और आपसी हित सदस्य देशों को आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने के लिए एक आम रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

एससीओ देशों के समान आर्थिक हित हैं जो सीधे उनकी सुरक्षा से जुड़े हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है और सदस्य राष्ट्र प्रमुख ऊर्जा निर्यातक हैं। एससीओ देशों की आर्थिक वृद्धि और विकास अन्य देशों को अपने संसाधनों का निर्यात करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए, सुरक्षा खतरों के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में कोई भी व्यवधान सदस्य राष्ट्रों के लिए गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकता है। क्षेत्र के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने में आपसी हित एससीओ देशों की स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

एससीओ देशों की एक साझा सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सदस्य देशों के गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं जो उनके सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ कर सकते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त सैन्य अभ्यास और शैक्षिक आदान-प्रदान सदस्य राष्ट्रों को एक-दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। सुरक्षा मुद्दों की आपसी समझ सदस्य राष्ट्रों को सुरक्षा मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक आम रणनीति विकसित करने में मदद कर सकती है। एससीओ देशों की सुरक्षा सीधे तौर पर आपसी हित और संयुक्त कार्रवाइयों पर निर्भर करती है। सदस्य देशों को सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने, अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एससीओ देशों में वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान देने में सक्षम एक अग्रणी क्षेत्रीय संगठन बनने की क्षमता है। इसलिए, सदस्य राष्ट्रों के लिए संगठन के लिए एक आम दृष्टि विकसित करना और इसे प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है।

> एससीओ देशों की आर्थिक वृद्धि और विकास अन्य देशों को अपने संसाधनों का निर्यात करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए, सुरक्षा खतरों के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में कोई भी व्यवधान सदस्य राष्ट्रों के लिए गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकता है।

किर्गिस्तान सक्रिय रूप से ताजिकिस्तान सहित एससीओ के सभी सदस्य देशों के साथ शांति और आपसी सहयोग चाहता है, जिसके साथ उसका सीमा संघर्ष रहा है। किर्गिस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति सद्भावना और सहयोग की स्थिति बनाए रखी है, विशेषकर ताजिकिस्तान के साथ सीमा विवाद के बाद। अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए किर्गिस्तान के प्रयास मध्य एशिया के दिल में इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति में निहित हैं। इस देश की सीमा चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। इस प्रकार, इसकी विदेश नीति अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग के माध्यम

से क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता से निर्धारित होती है। विदेशी संबंधों के लिए देश का दृष्टिकोण पारस्परिक सम्मान, समानता और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।

हाल के वर्षों में, किर्गिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ सीमा विवाद रहा है जिसके कारण दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच झड़पें हुई हैं। ये विवाद मुख्य रूप से भूमि और जल संसाधनों से संबंधित हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। तनाव के बावजूद, किर्गिस्तान ने हमेशा चर्चा और चर्चा के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों को हल करने की मांग की है।

एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंधों के प्रति किर्गिस्तान का दृष्टिकोण क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से भी आकार लेता है। देश आर्थिक पहलों में एक प्रमुख भागीदार है जिसका उद्देश्य बुनियादी संरचना के विकास और व्यापार के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है। किर्गिस्तान ने क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क के विकास में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे कि चीन-किर्गिस्तान-उजबेकिस्तान रेलवे परियोजना, जिसका उद्देश्य तीन देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है।

ताजिकिस्तान सहित एससीओ के सभी सदस्य देशों के साथ शांति और आपसी सहयोग के लिए किर्गिस्तान की इच्छा मध्य एशिया के दिल में अपनी रणनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए इसकी प्रतिबद्धता के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए देश का दृष्टिकोण पारस्परिक सम्मान, समानता और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों से निर्देशित होता है, जिसने पड़ोसियों के साथ सहयोग के सुदृढ़ संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद की है।

> एससीओ देश अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वे चीन के साथ आर्थिक सहयोग के महत्व को पहचानते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। इससे एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण बन गया है जिसमें एससीओ देशों को कई क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधनों के माध्यम से नेविगेट करना पड़ता है।

एससीओ देशों की राजनीतिक संभावनाओं को कारकों के एक जटिल सेट द्वारा आकार दिया जाता है, जिसमें भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां शामिल हैं।

संगठन ने आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में प्रगति की है, लेकिन ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। चूंकि भू-राजनीतिक माहौल बदल रहा है, एससीओ देशों को

अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधनों को नेविगेट करना चाहिए।

एससीओ को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कारकों में से एक अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा है। जैसा कि अमेरिका हिंद-प्रशांत की ओर बढ़ रहा है, चीन मध्य एशिया में तेजी से प्रभाव प्राप्त कर रहा है, जहां एससीओ आधारित है। इससे अमेरिका और एससीओ देशों के बीच कुछ तनाव पैदा हो गया है, विशेषकर जब चीन इस क्षेत्र में अपने बीआरआई का विस्तार करना जारी रखे हुए है। हालांकि एससीओ देश अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वे चीन के साथ आर्थिक सहयोग के महत्व को पहचानते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। इससे एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण बन गया है जिसमें एससीओ देशों को कई क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधनों के माध्यम से नेविगेट करना पड़ता है।

आर्थिक एकीकरण भी एससीओ देशों की राजनीतिक संभावनाओं को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। संगठन का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है और इस संबंध में प्रगति की है। हालांकि, एससीओ के भीतर आर्थिक एकीकरण की समस्याएं भी हैं। सदस्य देशों में आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर हैं, जिससे व्यापार और निवेश के अवसरों में असमानताएं हो सकती हैं।

एससीओ देशों के बीच आर्थिक संबंधों को विशिष्ट रूप से सुदृढ़ करने के लिए, विशिष्ट प्रस्तावों के साथ एससीओ देशों का एक बैंकिंग संघ बनाया जा सकता है। एक बैंकिंग संघ वित्तीय एकीकरण का एक रूप है जिसमें विभिन्न देशों में बैंकों के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षी तंत्र, एक जमा बीमा योजना और विवाद समाधान शक्तियों का निर्माण शामिल है।

यूरोपीय संघ (ईयू) में एक बैंकिंग संघ है जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और भविष्य के बैंकिंग संकटों को रोकना है। एससीओ देश अपनी आवश्यकताओं और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अपना बैंकिंग संघ बना सकते हैं।

एससीओ देशों के लिए एक बैंकिंग संघ बनाने में पहला कदम एक कानूनी संरचना का निर्माण होगा जो संघ के लक्ष्यों, दायरे और प्रबंधन संरचना को परिभाषित करता है। यह सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित संधि या समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। कानूनी संरचना को संघ की नियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों को भी परिभाषित करना चाहिए, जिसमें एससीओ देशों में काम करने वाले बैंकों को लाइसेंस और पर्यवेक्षण करने की शक्तियां शामिल हैं। दूसरा कदम एससीओ देशों के बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए एक एकीकृत तंत्र का निर्माण होगा। यह बैंकों के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की देखरेख और बैंकिंग नियमों और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह एससीओ सचिवालय में स्थित हो सकता है या एक अलग संगठन के रूप में बनाया जा सकता है। इसके पास उन बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी होनी चाहिए जो नियमों को तोड़ते हैं या वित्तीय प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा करते हैं। तीसरा कदम बैंक की विफलता की स्थिति में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक जमा बीमा योजना की स्थापना होगी जो गारंटी देता है कि जमाकर्ताओं को उनके बैंक के दिवालियापन के मामले में एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसे सदस्य बैंकों या संघ द्वारा स्थापित केंद्रीय निधि के योगदान से वित्त पोषित किया जा सकता है। उसे संकटग्रस्त बैंकों

में हस्तक्षेप करने और यदि आवश्यक हो तो बैंक का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का भी अधिकार होना चाहिए। चौथा कदम एक समाधान निकाय की स्थापना होगी जो संकटग्रस्त बैंकों के व्यवस्थित समाधान के लिए उत्तरदायी होगा। निपटान प्राधिकरण के पास बैंक विफलताओं में हस्तक्षेप करने और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रबंधन को संभालने की शक्ति होगी। निपटान प्राधिकरण के पास आवश्यक होने पर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने की शक्ति भी हो सकती है।

अंत में, एससीओ देशों को सूचनाओं के आदान-प्रदान और बैंकिंग नियमों और मानकों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक तंत्र बनाने की आवश्यकता है। इसमें एक समिति या कार्य समूह की स्थापना शामिल हो सकती है जो सूचना का आदान-प्रदान करने और नीति का समन्वय करने के लिए नियमित रूप से मिलती है।

एससीओ देशों के लिए एक बैंकिंग संघ के निर्माण के कई फायदे होंगे। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करके वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करेगा कि क्षेत्र में बैंक सामान्य नियमों और मानकों के अधीन हैं। दूसरा, यह नियामक बाधाओं को कम करके और सीमाओं के पार पूंजी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर सीमा पार बैंकिंग की दक्षता में सुधार करेगा। अंत में, यह क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बढ़ाएगा और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में विश्वास बढ़ाएगा।

अंत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एससीओ देशों में एक बैंकिंग संघ बनाने की क्षमता है जो आर्थिक सहयोग को गहरा कर सकता है और क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता में योगदान दे सकता है। एक बैंकिंग संघ की स्थापना के लिए एक कानूनी संरचना, एक एकीकृत निरीक्षण तंत्र, एक जमा बीमा योजना, एक विवाद समाधान निकाय और सूचना साझा करने और नीति समन्वय के लिए एक तंत्र की स्थापना की आवश्यकता होगी। जबकि बैंकिंग संघ के निर्माण की प्रक्रिया जटिल होगी और इसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी, संभावित लाभ एससीओ देशों के लिए इसे सार्थक बनाते हैं।

इसके अलावा, एससीओ के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों में से एक सीमा शुल्क संघ का निर्माण है। एक सीमा शुल्क संघ एक प्रकार का क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण है जिसमें संघ के भीतर बेची जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ और कोटा का उन्मूलन और संघ के बाहर से आयातित वस्तुओं पर एक सामान्य बाहरी टैरिफ लगाना शामिल है। विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया जा सकता है कि एससीओ देश अपना सीमा शुल्क संघ कैसे बना सकते हैं।

एससीओ देशों के बीच सीमा शुल्क संघ बनाने की दिशा में पहला कदम संघ की शर्तों पर सहमत होना होगा। इसमें एक सामान्य बाहरी टैरिफ पर सहमत होना और संघ के भीतर माल के मुक्त आवागमन के लिए नियमों को परिभाषित करना शामिल है। सदस्य राष्ट्रों को इस बात पर भी सहमत होने की

आवश्यकता है कि सामान्य बाहरी टैरिफ से उत्पन्न राजस्व को कैसे वितरित किया जाए। एससीओ देशों का सीमा शुल्क संघ बनाने का एक फायदा सदस्य देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। संघ के भीतर बेचे

जाने वाले सामानों पर टैरिफ और कोटा को हटाकर, व्यवसायों को एक-दूसरे के साथ व्यापार का विस्तार करने, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। टैरिफ और कोटा हटाने से उपभोक्ताओं के लिए सामान भी सस्ता होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

एससीओ देशों के सीमा शुल्क संघ बनाने का एक और लाभ विश्व बाजार में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। एक साथ काम करके, सदस्य राष्ट्र विकास और व्यापार विस्तार के लिए अधिक जगह के साथ एक बड़ा बाजार बना सकते हैं। यह क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा, जो आगे के आर्थिक विकास में योगदान देगा।

आर्थिक लाभों के अलावा, एससीओ देशों के एक सीमा शुल्क संघ के निर्माण से सदस्य राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंधों में भी सुधार हो सकता है। आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हुए, सदस्य राष्ट्र घनिष्ठ संबंध विकसित करेंगे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे।

> एससीओ देशों में एक बैंकिंग संघ बनाने की क्षमता है जो आर्थिक सहयोग को गहरा कर सकता है और क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता में योगदान दे सकता है

हालांकि, कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें एससीओ देशों को एक सफल सीमा शुल्क संघ बनाने के लिए हल करने की आवश्यकता है। एक समस्या यह है कि सदस्य राष्ट्रों के पास आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर हैं, जो एक सामान्य बाहरी टैरिफ पर सहमत होना मुश्किल बना सकते हैं जो सभी सदस्यों के लिए उचित है। यह जोखिम भी है कि कुछ सदस्य राष्ट्र अन्य सदस्यों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क संघ का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। एक और मुद्दा यह है कि सदस्य राष्ट्रों के पास अलग-अलग कानूनी और नियामक संरचना हैं, जो संघ के भीतर व्यापार के लिए नियमों और विनियमों को सुसंगत करना मुश्किल बना सकते हैं। इससे संघ के भीतर अक्षमता और व्यापार बाधाएं पैदा हो सकती हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, एससीओ देशों के एक सीमा शुल्क संघ का निर्माण इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है। सफल होने के लिए, सदस्य राष्ट्रों को संघ की शर्तों पर चर्चा करने और उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने में, वे एक अधिक समृद्ध और स्थिर क्षेत्र बना सकते हैं जो सभी सदस्य राष्ट्रों को लाभान्वित करेगा।

अंत में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपरोक्त सभी केवल अध्येता की दृष्टि है कि एससीओ देश कैसे विकसित हो सकते हैं। हालांकि ये विचार इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक लाभ ला सकते हैं, लेकिन यह अंतिम योजना नहीं है। एससीओ के सदस्य देशों को लाभों और चुनौतियों के बारे में खुली और ईमानदार चर्चा करने और एक ऐसे समाधान के साथ आने की आवश्यकता होगी जो सभी संबंधित देशों के लिए सबसे उपयुक्त हो।

भारतीय वैश्विक परिषद

एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद - 2023

S | E | C | U | R | E | SCO

शंघाई सहयोग संगठन एक नए भूराजनीतिक वातावरण में

अखिल-यूरेशिया सहयोग की संस्था बन रहा है?

दिमित्री पावलोविच नोविकोव

नवीन भू-राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में एससीओ

शंघाई सहयोग संगठन 20 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। इसकी स्थापना पर घोषणा पर छह राष्ट्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे: चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उजबेकिस्तान 15 जून 2001 को शंघाई में। एक दिन पहले शंघाई के जिनजियांग होटल के छोटे से असेंबली हॉल में तत्कालीन चीनी नेता जियांग जेमिन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट करके द्विपक्षीय संबंधों के विकास और एससीओ के लक्ष्यों पर चर्चा की थी। दिलचस्प बात यह है कि एक ही हॉल में, लेकिन लगभग तीन दशक पहले, फरवरी 1972 में, अमेरिकी राष्ट्रपति आर निक्सन और चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने पीआरसी और अमेरिका के बीच प्रसिद्ध शंघाई विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए। इसलिए, इस बैठक को दोगुना प्रतीकात्मक कहा जा सकता है। सबसे पहले, यह प्रदर्शित किया गया कि यह रूसी-चीनी रणनीतिक सहयोग था जिसने एससीओ के निर्माण के लिए आधार प्रदान किया; दूसरे, यह दर्शाता है कि मॉस्को और बीजिंग के लिए शीत युद्ध के वर्ष अतीत में बहुत दूर थे और रूस और चीन दुनिया को द्विध्रुवीयता और अमेरिका के प्रभुत्व वाले एकध्रुवीयता से दूर वास्तविक बहुध्रुवीयता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

एससीओ ने दो दशकों से अधिक समय के काम में एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआत से, यूरेशियन अंतरिक्ष के एक क्षेत्रीय संगठन की इसकी अवधारणा गतिविधि के तीन मुख्य क्षेत्रों पर आधारित थी: सुरक्षा और विदेश नीति सहयोग की तीव्रता, मानवीय क्षेत्र (संस्कृति, विज्ञान, खेल, आदि) में आर्थिक सहयोग और सहयोग को गहरा करना।

2022 की भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में प्रमुख संरचनात्मक बदलाव किए हैं, जो एससीओ के महत्व को और बढ़ाता है और इसके विकास के लिए नए अवसर खोलता है। हालांकि, इन भू-राजनीतिक परिवर्तनों को सिर्फ नई चुनौतियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि मौलिक रूप से नई अंतरराष्ट्रीय संरचना के तरीके के रूप में माना जाना चाहिए। यह एससीओ से न केवल खुद को एक नई वास्तविकता में अपनाने की मांग कर सकता है, बल्कि बहुत मौलिक तरीके से अपनी संरचनात्मक और संस्थागत भूमिका पर पुनर्विचार कर सकता है। इन घटनाक्रमों की प्रवृत्ति मध्य एशियाई मुद्दों पर केंद्रित संगठन से एक अखिल-यूरेशिया सहयोग संस्थान में एससीओ का एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। यह संस्था महाद्वीप के गैर-पश्चिमी भाग में ओएससीई के किसी प्रकार के सादृश्य के रूप में काम कर सकती है, लेकिन कम अस्पष्ट और अधिक केंद्रित और प्रभावी है। यह सार्थक विकास तीन मुख्य मार्गों पर आगे बढ़ सकता है: क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक और विशेषज्ञ वार्ता को गहरा करना।

एससीओ सुरक्षा ट्रैक: एक नए वातावरण के अनुकूल

इन तीन क्षेत्रों में संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धियां सुरक्षा के क्षेत्र में रही हैं। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों का समापन किया गया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में समन्वय विशेष महत्व का है। एससीओ के सभी सदस्य देशों पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों ने हमला किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन द्वारा अफगानिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल की वापसी की घोषणा के साथ ही यह खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा मुद्दों में नशीली दवाओं की तस्करी, सूचना सुरक्षा और अवैध प्रवास की समस्याओं का मुकाबला करने के रूप में एससीओ गतिविधि के ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं।

सैन्य क्षेत्र में सहयोग विकसित हो रहा है, सदस्य राष्ट्रों के सशस्त्र बलों "शांति मिशन" के संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ-साथ विशेष सेवाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अभ्यास लगभग प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे हैं। 2018-2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की काउंटरनारकोटिक्स रणनीति के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एससीओ सदस्य देशों के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय काउंटरनारकोटिक्स ऑपरेशन "वेब" आयोजित किया गया था, जिसे 2019 में बिश्केक में अपनाया गया था।

ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के संरचना के भीतर समन्वय एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जैसा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर 2021 में दुशांबे में राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक में अपने भाषण में उल्लेख किया था, "एससीओ बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वास्तुकला के सबसे प्रभावशाली केंद्रों में से एक है, जो यूरेशियन क्षेत्र की सुरक्षा, इसके स्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास और सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है[12]।

> संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धियां सुरक्षा के क्षेत्र में रही हैं। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों का समापन किया गया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में समन्वय विशेष महत्व का है।

2022 में शुरू हुई भू-राजनीतिक उथल-पुथल एससीओ सुरक्षा एजेंडे को अपरिहार्य रूप से व्यापक बनाएगी। यह अपरिहार्य रूप से रणनीतिक आश्वासन और सैन्य मुद्दों और सैन्य सहयोग पर किसी प्रकार की चर्चा जैसे मुद्दों को मेज पर लाएगा-जिसे एससीओ ने पारंपरिक रूप से टालने की कोशिश की थी। संगठन के विस्तार द्वारा दो अन्य महत्वपूर्ण पहलू पूर्व निर्धारित हैं। ईरान की सदस्यता अपरिहार्य रूप से मध्य पूर्व क्षेत्रीय सुरक्षा को एससीओ के लिए आवश्यक विषयों में से एक के रूप में लाती है, कम से कम कुछ पहलुओं

में, जैसे कि आतंकवाद विरोधी प्रथाएं। पश्चिम के साथ टकराव में रूस की भागीदारी और बेलारूस में एससीओ का विस्तार एससीओ एजेंडा को यूरोपीय सुरक्षा मुद्दों पर ले जाता है-कम से कम कुछ पहलुओं में एक बार फिर। यह सब एससीओ को एक अधिक व्यापक अखिल-यूरेशिया सुरक्षा और सहयोग संस्थान में बदलने के लिए एक आधार बनाता है। लेकिन अपनी प्रथाओं का विस्तार और गहन करते समय सुरक्षा पर बहुत सुदृढ़ ध्यान देने से बचने के लिए, एससीओ को आर्थिक सहयोग का ट्रैक भी विकसित करना चाहिए।

एससीओ आर्थिक ट्रैक: घोषणाओं से कार्यों तक

एससीओ के भीतर आर्थिक सहयोग शायद सबसे कठिन विषय है। यहां संगठन अभी तक महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पाया है। वर्षों से, सदस्य राष्ट्रों में विशेषज्ञ और राजनेता एससीओ विकास बैंक की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुपक्षीय अंतर-राष्ट्र आर्थिक परियोजनाओं का वित्तपोषण कर सकता है। लेकिन अब तक केवल एक संधि आधार स्थापित किया गया है: केवल मुट्ठी भर बहुपक्षीय परियोजनाएं, ज्यादातर परिवहन और रसद क्षेत्रों में, उस आधार पर लागू की जा रही हैं।

हालांकि, नए भू-राजनीतिक माहौल में, जब एससीओ ने अस्तित्व के दो दशकों में जो सभी सकारात्मक चीजें बनाई हैं, उन्हें संरक्षित करना अनिवार्य है, तो बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग की तीव्रता संगठन के आगे के विकास के लिए अस्तित्ववादी नहीं कहने के लिए काफी आवश्यक हो गई। सबसे पहले, यह एससीओ के आगे संस्थागतकरण और साझेदारी के लिए एक स्पष्ट गैर-टकराव एजेंडा के लिए एक नया आवेग पैदा कर सकता है। दूसरे, यह किसी भी तरह सुरक्षा मुद्दों पर भारी ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोग के एक आवश्यक क्षेत्र के रूप में काम कर सकता है। मौजूदा माहौल में, जिसमें एससीओ देश कुछ आशंकाओं के साथ देखते हैं, एक साझा सुरक्षा एजेंडे को बढ़ावा देने के प्रयासों को पहले की तरह उत्साह के साथ पूरा किए जाने की संभावना नहीं है। इस स्थिति में सुरक्षा एजेंडा को सुदृढ़ करना, जिसमें कठोर सुरक्षा पर चर्चा के संभावित (वास्तव में आवश्यक) हस्तक्षेप के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

रसद सहयोग का प्रमुख क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि यह शायद सबसे निष्पक्ष रूप से आवश्यक पहलू है, जिसका एससीओ संरचना के भीतर चर्चा का एक लंबा इतिहास है। वास्तव में, रसद हमेशा आर्थिक एजेंडे के केंद्र में रहा।

उदाहरण के लिए, एससीओ प्रधानमंत्रियों की 21वीं बैठक के बाद अंतिम संयुक्त विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "सड़क और रेल परिवहन, मल्टीमॉडल परिवहन गलियारों और रसद केंद्रों के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मार्गों के साथ-साथ डिजिटल, अभिनव और ऊर्जा-बचत प्रक्रियाओं को पेश करने के लिए नए और उन्नत, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार सीमा पार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए जो पारस्परिक रूप से लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करते हैं। एससीओ सदस्य राष्ट्रों की पारगमन क्षमता"[13]।

जमीनी स्तर पर लगभग सभी हितधारकों के साथ, एससीओ उत्तर-पूर्व और पूर्व-पश्चिम लॉजिस्टिक गलियारों के साथ-साथ उनके बीच संभावित संश्लेषण जैसी परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए सबसे स्वाभाविक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। मुख्य समस्या यह है कि वर्षों से एससीओ वार्ता और सौदों के लिए एक वास्तविक आधार के बजाय घोषणात्मक समर्थन का स्रोत था। लेकिन क्षेत्रीय रसद के विकास में बढ़ती इंटरकनेक्टिविटी और उद्देश्य आवश्यकता के संदर्भ में, संगठन के पास ऐसी परियोजनाओं के संस्थागतकरण और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाने की एक बड़ी क्षमता है।

आर्थिक एजेंडे का एक और महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा वार्ता और सहयोग है, संभवत: एससीओ ऊर्जा क्लब के संरचना के भीतर। एससीओ ऊर्जा क्लब के लिए मुख्य कार्य इसका पूर्ण संस्थागतकरण है। फिलहाल, एससीओ के भीतर यह संरचना मुख्य रूप से प्रकृति में सलाहकार है, जो एससीओ सदस्य राष्ट्रों के उप ऊर्जा मंत्रियों और इस संगठन के सहयोगी सदस्यों द्वारा विभिन्न ऊर्जा मुद्दों की चर्चा के लिए एक प्रकार के अतिरिक्त मंच के रूप में कार्य करती है। नवंबर 2022 में, एससीओ परिषद की सरकार के प्रमुखों की एक बैठक में, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने कहा कि एससीओ ऊर्जा क्लब का उपयोग "ऊर्जा क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने के लिए" अधिक सक्रिय रूप से किया जाना चाहिए[14]।

एससीओ ऊर्जा सहयोग का अर्थ है ऊर्जा रणनीतियों का सामंजस्य और हाइड्रोकार्बन उत्पादक देशों रूस, ईरान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान और उपभोक्ता देशों-चीन, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना। वास्तव में, कई विशेषज्ञों के अनुसार, एससीओ ऊर्जा क्लब एससीओ को आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली में बदलने में योगदान दे सकता है[15]। तुर्की को एक गैस हब में बदलने की योजना जिसके माध्यम से पाइपलाइन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का व्यापार किया जाएगा, दोनों यूरोपीय दिशा में और क्षेत्रीय-यूरेशियन स्तर पर एससीओ ऊर्जा क्लब के आगे के विकास में भी योगदान देना चाहिए।

> एससीओ ऊर्जा सहयोग का अर्थ है ऊर्जा रणनीतियों का सामंजस्य और हाइड्रोकार्बन उत्पादक देशों और उपभोक्ता देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना। वास्तव में, कई विशेषज्ञों के अनुसार, एससीओ एनर्जी क्लब एससीओ को आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली में बदलने में योगदान दे सकता है।

ऊर्जा संवाद का दूसरा पहलू इस क्षेत्र में नियमों का विकास है। 2022 में भू-राजनीतिक टकराव के उदय के साथ वैश्विक क्षेत्रीय व्यवस्था में भी गिरावट शुरू हो गई। रूस के खिलाफ पश्चिमी ऊर्जा प्रतिबंध वास्तव में विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के लिए वैश्विक ऊर्जा बाजार के सशक्त परिवर्तन के लिए मिसाल के रूप में काम कर सकते हैं। एससीओ जिसमें दो प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता-चीन और भारत-और अग्रणी ऊर्जा उत्पादकों में से एक-रूस शामिल हैं-ऊर्जा क्षेत्र में नियम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। वास्तव में, यह ऊर्जा सुरक्षा पर वर्तमान एससीओ चर्चा के साथ पूरी तरह

से संबंधित है जो इन विचारों के आसपास भी विकसित होता है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा सुरक्षा पर एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के अंतिम वक्तव्य में "खुले, पारदर्शी और कुशल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, व्यापार बाधाओं को कम करने, ऊर्जा क्षेत्र में विनिमय वस्तुओं पर वैश्विक कीमतों की अत्यधिक अस्थिरता से बचने" और "आपूर्ति करने वाले देशों, पारगमन देशों और उपभोक्ता देशों के बीच चर्चा को सुदृढ़ करने" की आवश्यकता पर स्पष्ट जोर दिया गया था[16]। ब्रिक्स के साथ एससीओ नीतियों का एक विशेष समन्वय और संश्लेषण इन प्रयासों को और भी प्रभावी बना सकता है। विशेष रूप से सऊदी अरब की एक सक्रिय इच्छा को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रारूपों के साथ साझेदारी विकसित करने के लिए।

नए नियमों पर चर्चा एक आदेश बनाने वाले संगठन के रूप में व्यापक अर्थों में आवश्यक हो सकती है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां एससीओ के कुछ राष्ट्र पश्चिमी प्रतिबंधों से पीड़ित हैं और अन्य द्वितीयक प्रतिबंधों से पीड़ित हैं, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य समस्याओं के कारण आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट आई है, इन खतरों को रोकने के लिए आर्थिक सहयोग को गहरा करना सभी के लिए आवश्यक है।

रूस और अन्य सदस्य देशों में एससीओ के विशेषज्ञों ने एससीओ के आर्थिक घटक के त्वरित विकास की वकालत की है क्योंकि इसकी गतिविधियां क्षेत्रीय संगठन के रूप में हैं। चीन और मध्य एशियाई राष्ट्रों ने हमेशा आधिकारिक स्तर पर आर्थिक सहयोग का समर्थन किया है, हालांकि अलग-अलग तरीकों से: चीन ने "माल, पूंजी, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के मुक्त आंदोलन के क्रमिक कार्यान्वयन" के लिए शर्तों के शीघ्र निर्माण पर जोर दिया है-एससीओ चार्टर[17] में निर्धारित एक लक्ष्य-वास्तव में, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण। यह केवल स्वाभाविक है, क्योंकि शक्तिशाली चीनी उद्योग को बाजारों के विस्तार की आवश्यकता है। मध्य एशियाई राष्ट्रों ने अधिक सतर्क रुख अपनाया है।

व्यवहार में, हालांकि, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग का गंभीरता से विस्तार करने के ये विचार अक्सर रूस सहित कई देशों में सोच की जड़ता के खिलाफ चलते हैं। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अगर एससीओ के भीतर अधिक प्रमुख बहुपक्षीय आर्थिक परियोजनाएं थीं, तो रूस के लिए प्रतिबंधों की चुनौतियों का जवाब देना बहुत आसान होगा।

यह आशा की जानी चाहिए कि कई नई प्रमुख आर्थिक शक्तियों का प्रवेश, जिनमें से कुछ पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत भी हैं, एससीओ की अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की तीव्रता को प्रोत्साहित करेगा, जो इसे और सुदृढ़ करेगा और इसे आम जनता के लिए अधिक व्यावहारिक रूप से प्रासंगिक बनाएगा।

एससीओ विज्ञान और विशेषज्ञ ट्रैक: नए विचारों के लिए एक आधार के रूप में कार्यरत

जबकि एससीओ को नए भू-राजनीतिक वातावरण में अपनी संरचनात्मक भूमिका पर काफी मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता है, सदस्य-राष्ट्रों के लिए एससीओ संस्थागत विकास की एक नई रणनीति के

साथ आने के लिए विशेषज्ञ वार्ता आवश्यक हो जाती है। अपने अस्तित्व के दौरान, एससीओ ने अपने आसपास सार्वजनिक संरचनाओं का एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। संगठन के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक और व्यावसायिक संरचनाएं उभरी हैं। इनमें एससीओ बिजनेस काउंसिल, एससीओ यूथ काउंसिल, एससीओ इंटरबैंक एसोसिएशन और कुछ अन्य शामिल हैं।

हालांकि, शायद सबसे अधिक मांग में से एक अनुसंधान-विशेषज्ञ पारिस्थितिकी तंत्र है। आज दुनिया में शायद कोई गंभीर अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है जो "दूसरे ट्रैक" के तंत्र का उपयोग नहीं करता है- संगठन की समस्याओं से निपटने और इसे वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता प्रदान करने वाले वैज्ञानिक केंद्रों और विशेषज्ञों का एक संघ। इस तरह की संरचनाएं मौजूद हैं, उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र, आसियान, एपेक, सीएसटीओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तहत।

शंघाई सहयोग संगठन के मामले में, एससीओ फोरम यह भूमिका निभाता है। इसके संस्थापक दस्तावेजों के अनुसार, फोरम एक बहुपक्षीय, सार्वजनिक सलाहकार और विशेषज्ञ तंत्र है जो एससीओ गतिविधियों को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक रूप से समर्थन करने, एससीओ सदस्य राष्ट्रों के अनुसंधान और राजनीति विज्ञान केंद्रों के बीच सहयोग विकसित करने, संगठन की क्षमता में सामयिक मुद्दों पर संयुक्त शोध करने, एससीओ गतिविधियों के उद्देश्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करने, अकादमिक और सार्वजनिक हलकों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए स्थापित किया गया है। और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विद्वानों और विशेषज्ञों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना। फोरम एससीओ सदस्य देशों के कानून और एससीओ नियमों के आधार पर एससीओ चार्टर के सिद्धांतों पर अपनी गतिविधियों का निर्माण करेगा। फोरम एससीओ सचिवालय, राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद और एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करता है।

फोरम की स्थापना 2006 में मास्को में इसकी स्थापना बैठक में हुई थी, और उसी वर्ष, 'एससीओ- सफल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक नया मॉडल' नामक एक लेख में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिखा कि "हाल ही में स्थापित एससीओ फोरम, जिसने विशेषज्ञ और अकादमिक हलकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया, का उद्देश्य संगठन का एक प्रकार का गैर-सरकारी विशेषज्ञ तंत्र बनना है[18]।

और दो साल बाद, बीजिंग में फोरम की तीसरी बैठक में बोलते हुए, तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री यांग जिएची ने कहा: "दो वर्षों के दौरान, विभिन्न प्रकार के आदान-प्रदान, चर्चाओं और द्विपक्षीय कार्यक्रमों का आयोजन करके, फोरम ने सूचना, विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया है और विभिन्न प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है। सरकारी एजेंसियों को निर्णय लेने के लिए उपयोगी सुझाव और आधार प्रदान करके, इसने एससीओ के विकास में बहुत योगदान दिया है। चीनी पक्ष इसकी सराहना करता है[19]।

प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व फोरम में एक अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है जो एससीओ अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे आधिकारिक है। इसे एससीओ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के रूप में नामित किया गया है और इस तरह, फोरम का सदस्य है। आज, फोरम के भीतर आठ एससीओ सदस्य और आठ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। फोरम में शामिल होने वाले पहले लोग कजाकिस्तान गणराज्य के पहले राष्ट्रपति की नींव के तहत विश्व अर्थव्यवस्था

और राजनीति संस्थान, चीनी विदेश मंत्रालय के तहत चीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, और रूसी विदेश मंत्रालय के मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के पूर्वी एशियाई और एससीओ अध्ययन केंद्र उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के तहत रणनीतिक और अंतरक्षेत्रीय अध्ययन संस्थान थे। 2018 में एससीओ में भारत और पाकिस्तान के औपचारिक प्रवेश के बाद, नई दिल्ली में भारतीय वैश्विक परिषद और इस्लामाबाद के रणनीतिक अध्ययन संस्थान को फोरम में भर्ती कराया गया था।

इसके अलावा, वैज्ञानिक-विशेषज्ञ ट्रैक का विकास दो मुख्य दिशाओं का पालन करने की संभावना है। सबसे पहले, एससीओ फोरम संगठन के आगे के विकास के लिए एक रणनीति को विस्तृत करने के लिए एक मंच बन सकता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अपनी संस्थागत भूमिका को सुदृढ़ करना है। इसका अर्थ न केवल एससीओ फोरम की भूमिका को सुदृढ़ करना है, बल्कि दूसरे ट्रैक के भीतर एससीओ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ संस्थानों के बीच संबंधों की तीव्रता को मौलिक रूप से बढ़ाना भी है।

> एक महत्वपूर्ण क्षेत्र एससीओ दक्षताओं में विशेषज्ञों का एक व्यापक नेटवर्क बनाने के लिए दूसरे ट्रैक के भीतर वैज्ञानिक और शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। एक अच्छा उदाहरण युवा विद्वानों, एससीओ और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों के विशेषज्ञों के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय का 2023 अध्यक्षता फैलोशिप कार्यक्रम है। संपर्कों के ऐसे नेटवर्क को विकसित करने और गहरा करने से न केवल विशेषज्ञता की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि नागरिक समाजों के बीच संबंध भी सुदृढ़ होंगे।

एक दूसरा कम महत्वपूर्ण क्षेत्र एससीओ दक्षताओं में विशेषज्ञों का एक व्यापक नेटवर्क बनाने के लिए दूसरे ट्रैक के भीतर वैज्ञानिक और शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। एक अच्छा उदाहरण युवा विद्वानों, एससीओ और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों के विशेषज्ञों के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय का 2023 अध्यक्षता फैलोशिप कार्यक्रम है। संपर्कों के ऐसे नेटवर्क को विकसित करने और गहरा करने से न केवल विशेषज्ञता की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि नागरिक समाजों के बीच संबंध भी सुदृढ़ होंगे। यह गतिविधि क्षेत्र बदले में, अन्य एससीओ ट्रैक के विकास का आधार बन सकता है।

एससीओ ग्रेटर यूरेशिया की संस्थागत रीढ़ के रूप में

फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेनी संकट के नए दौर ने पूरी दुनिया की भू-राजनीतिक स्थिति को गंभीरता से बदल दिया है। आज दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है। ये चुनौतियां एक तरफ बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करने वाली ताकतों के तेज ध्रुवीकरण और समेकन से जुड़ी हैं, और दूसरी तरफ,

जो अमेरिकी आधिपत्य का समर्थन करती हैं। जिन राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले एक मध्यवर्ती स्थिति ली थी और दोनों प्रवृत्तियों के समर्थकों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी, उन्हें एक स्पष्ट विकल्प बनाना पड़ा और दूसरे के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण रुख लेते हुए उनमें से एक में शामिल होना पड़ा।

नया संदर्भ एशिया और यूरेशिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रारूपों के भाग्य का सवाल भी उठाता है: एपेक फोरम, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और निश्चित रूप से, एससीओ। उनमें से कुछ के शिखर सम्मेलनों में रूस के प्रतिनिधित्व पर हालिया विवादों को याद करना पर्याप्त है। नतीजतन, इन मंचों का काम काफी कमजोर हो सकता है, जो प्रभावी बहुपक्षीय प्रारूपों के बिना इस क्षेत्र को छोड़ सकता है। इन परिस्थितियों में, एससीओ का प्रभावी और कुशल काम नया महत्व लेता है।

ऊपर वर्णित क्षेत्रों का विकास एक प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मंच के रूप में एससीओ की क्षमता के संभावित अनलॉक का केवल एक हिस्सा है। संगठन के आगे के विकास के लिए प्रमुख रणनीतिक कार्य क्षेत्रीय और वैश्विक प्रक्रियाओं की मुख्यधारा की विकास प्रक्रियाओं में इसका जैविक समावेश होना चाहिए जो 2022 में काफी तेज हो गए हैं। मुख्य प्रक्रिया यूरेशिया में एक मेगा-क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देना है जिसका उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना और महाद्वीप के गैर-पश्चिमी हिस्से की विशाल क्षमता विकसित करना होगा।

इस संदर्भ में, यूरेशियन महाद्वीप पर मुख्य रूसी मेगा-पहल, जिसका उद्देश्य इस क्षमता को साकार करना है, वास्तव में पहले से ही एक ग्रेटर यूरेशिया सह-विकास और सुरक्षा समुदाय बनाने का विचार बन गया है-आसियान देशों और कोरिया गणराज्य और संभवतः जापान से पूर्व में, भारत से दक्षिण में, तुर्की और ईरान, जिसके मुख्य स्तंभ रूस हैं। ईएईसी और चीन, साथ ही एससीओ निश्चित रूप से।

शंघाई सहयोग संगठन इस क्षेत्र की सबसे अच्छी राजनीतिक रीढ़ और आम सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रतीत होता है, विशेषकर भारत और पाकिस्तान में और संभावित रूप से ईरान में इसके विस्तार के बाद। उसी समय, जैसा कि ऊपर चित्रित किया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उदाहरण के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में। यह आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में खेल के नियमों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी हो सकता है, जो अनिवार्य रूप से बढ़ना निश्चित लगता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के नए पैटर्न में, जो रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों द्वारा आकार लिया गया है, चीन और ईरान अलग-थलग हैं और अनिवार्य रूप से कुछ अपवादों के साथ एक-दूसरे की ओर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र के सबसे कम विकसित देशों-पाकिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्यों में कम शुरुआत के प्रभाव के कारण तेजी से आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं। यही बात ईरान पर भी लागू होती है, जो कई वर्षों के बाद प्रतिबंधों से उभर रहा है और तेजी से विकास के लिए लगभग "बर्बाद" है। और चीन और भारत की विशाल अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक "सुरक्षा कुशन" के साथ सह-विकास का नया स्थान प्रदान करती हैं।

काफी हद तक, कई रूसी पहलों का उद्देश्य ऐसी जगह बनाना था, उदाहरण के लिए, ईएईयू-पीआरसी व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौते को समाप्त करने की पहल, और आसियान के साथ सहयोग की तीव्रता। इस क्षेत्र

में केंद्रीय पहल रूस के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में शुरू की गई पहल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन का ग्रेटर यूरेशियन आर्थिक क्षेत्र (जीईईए) बनाने का प्रस्ताव इस दिशा में एक केंद्रीय पहल थी और साथ ही एक ग्रेटर यूरेशियन साझेदारी बनाने का उनका प्रस्ताव भी था[20]। इस पहल को एससीओ के सदस्य देशों द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है, जैसा कि संयुक्त अंतरराज्यीय घोषणाओं में परिलक्षित होता है। हालांकि, इसे अभी भी आगे के कार्यान्वयन के लिए ठोस रूप से तैयार करने की आवश्यकता है।

> ग्रेटर यूरेशिया समुदाय का उद्भव और विकास पूरी तरह से एक रूसी योजना या आकांक्षा नहीं है। यह प्रमुख वैश्विक भू-राजनीतिक रुझानों पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसका आधार रूसी-चीनी तालमेल है, जो चीन के उदय, यूएसएसआर के पतन और नए रूस को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पश्चिमी प्रभुत्व की स्थापना के संरचना के भीतर दोनों राष्ट्रों के विकास को रोकने के प्रयासों की सक्रिय उत्तेजना से प्रेरित है।

यूरेशिया में उभरा संस्थागत वातावरण, जिसमें आंशिक रूप से अतिव्यापी और आंशिक रूप से परस्पर विरोधी पहल शामिल हैं, वर्तमान में इस क्षेत्र में राष्ट्रों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है: सतत विकास, राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह वातावरण पैचवर्क है और इसे अधिक अभिव्यक्ति/संयुग्मन की आवश्यकता है।

ग्रेटर यूरेशिया समुदाय का उद्भव और विकास पूरी तरह से एक रूसी योजना या आकांक्षा नहीं है। यह प्रमुख वैश्विक भू-राजनीतिक रुझानों पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसका आधार रूसी-चीनी तालमेल है, जो चीन के उदय, यूएसएसआर के पतन और नए रूस को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पश्चिमी प्रभुत्व की स्थापना के संरचना के भीतर दोनों राष्ट्रों के विकास को रोकने के प्रयासों की सक्रिय उत्तेजना से प्रेरित है। इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों के अपने हित हैं, जो उन्हें बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से मुक्त एक नई यूरेशियन प्रणाली के निर्माण में अधिक शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

नए संदर्भ में, एससीओ को यूरेशियन समेकन की प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका को परिभाषित करने की आवश्यकता है। ग्रेटर यूरेशिया के अधिकांश प्रस्तावित दृष्टिकोण मानते हैं कि यह नया समुदाय यहां मौजूदा और अच्छी तरह से स्थापित संगठनों और समूहों पर निर्माण करेगा: ईएईयू, एससीओ, सीएसटीओ, आसियान और संभवतः एपेक। इसका तात्पर्य सबसे आधिकारिक यूरेशियन संरचनाओं में से एक के रूप में एससीओ के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि, क्या यह भूमिका अधिक राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक और सभ्यतागत है, यह गंभीर बहस का विषय है।

हमें ऐसा लगता है कि एससीओ यूरेशियन सहयोग के संकेंद्रित मंडलों में एक दूसरे सर्कल की भूमिका निभा सकता है, जो तीव्रता में भिन्न होगा। विभिन्न यूरेशियन राष्ट्र असमान रूप से यूरेशियन सहयोग में संलग्न होने के लिए तैयार हैं: कुछ एकीकरण और यहां तक कि एक राजनीतिक गठबंधन चाहते हैं, जबकि अन्य केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। और इस संबंध में, कम से कम शुरू में, कठोर मानदंडों से बचा जाना चाहिए, जैसा कि अभ्यास है, उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ या नाटो में, जहां इस वजह से गंभीर आंतरिक समस्याएं पहले से ही उत्पन्न हुई हैं।

निष्कर्ष

इन परिस्थितियों में, संकेंद्रित मंडलियों की एक प्रणाली, प्रत्येक राष्ट्र को यूरेशियन प्रणाली से जुड़ने की अनुमति देती है जब वह तैयार होती है, बहुत रचनात्मक लगता है। यहां भी एससीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब यह स्पष्ट है कि यूरेशियन प्रणाली का मूल ईएईयू और चीन के बीच घनिष्ठ चर्चा होगी। हालांकि, यह भारत, आसियान और भविष्य में, संभवतः यूरोपीय संघ या उसके व्यक्तिगत सदस्यों जैसे अन्य प्रमुख नायकों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव होने की संभावना नहीं है। और यहां एससीओ की भूमिका अमूल्य होगी। यह भूमिका यह होगी कि एससीओ के माध्यम से कुछ राष्ट्र जो ईएईयू का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन या तो एससीओ के पूर्ण सदस्य हैं या पर्यवेक्षक और संवाद भागीदार हैं, यूरेशियन सहयोग की प्रणाली में शामिल हो सकते हैं। और अगला, तीसरा सर्कल, उन राष्ट्रों से मिलकर बनेगा जो न तो एससीओ के सदस्य हैं और न ही ईएईयू के। एससीओ विशेषज्ञ इस अवधारणा के विस्तृत विस्तार में संलग्न हो सकते हैं।

एससीओ के 20 वर्षों के काम से पता चला है कि संगठन न केवल एक परिणाम बन गया है, बल्कि यूरेशिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंजनों में से एक है। उस समय में यह एक लंबा सफर तय कर चुका है और अब दुनिया भर में काफी रुचि आकर्षित कर रहा है। उसी समय, यह रुचि कुछ मायनों में उससे भी अधिक है जो संगठन की वास्तविक उपलब्धियां उत्पन्न कर सकती हैं। हाल के घटनाक्रम, वैश्विक अशांति में वृद्धि और तेजी से तेज भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एससीओ के आगे के विकास और वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था के केंद्रीय संस्थागत स्तंभों में से एक में परिवर्तन को गति दे सकती है।

पिछले दो दशकों में, एससीओ ने कद में काफी वृद्धि की है, जो गैर-पश्चिमी दुनिया में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक बन गया है। संगठन में रुचि का कारण यह है कि इसने कई अन्य गैर-पश्चिमी संरचनाओं के साथ, दुनिया में पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने की भूमिका निभाई है, जिसे यूएसएसआर 10 के पतन के बाद खाली छोड़ दिया गया था[21]। हालांकि, इसकी अपनी गतिविधियों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो शोफील्ड संरचनाओं की प्रभावशीलता को साबित करती है।

फिलहाल यह बहुत स्पष्ट है कि, इसके बावजूद, सुरक्षा डोमेन एससीओ में सबसे विकसित और सबसे उन्नत है। हालांकि, तब से दुनिया में स्थिति काफी खराब हो गई है। इसलिए, जो बनाया गया है उसका गंभीर रूप से आकलन करते समय, हम मानते हैं कि यद्यपि संगठन के भीतर राजनीतिक संवाद उच्च

स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन किए गए निर्णयों का व्यावहारिक कार्यान्वयन कभी-कभी रुक गया है, और राष्ट्र के प्रमुखों द्वारा किए गए राजनीतिक और आर्थिक समझौते अक्सर मूर्त रूप लेने में विफल रहे हैं। इस संबंध में, सभी एससीओ निकायों को उनकी मात्रा के बजाय अपनाए गए दस्तावेजों की गुणवत्ता और व्यवहार्यता पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और शायद उन्हें प्रमुख रणनीतिक दस्तावेजों तक कम करना होगा।

तार्किक आंतरिक विकास के ठोस उपायों के रूप में, उदाहरण के लिए, एससीओ राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए एससीओ यूनिवर्सल सेंटर में आरएटीएस के पहले परिकल्पित पुनर्गठन को लागू करना उपयोगी होगा।

2021 में दुशांबे में बोलते हुए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अपने कर्मचारियों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार का मुकाबला करने में विशेषज्ञों को शामिल करके क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरएटीएस की कार्यात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी मानता है[22]। इन सभी क्षेत्रों में सदस्य देशों से रचनात्मक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए, कजाकिस्तान ने बिश्केक में एक सूचना सुरक्षा केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया है और ताजिकिस्तान ने दुशांबे में एक एंटी-ड्रग सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इन सभी प्रस्तावों का स्वागत है, लेकिन बलों को तितर-बितर न करने और समग्र समन्वय बनाए रखने के लिए, सभी नई संरचनाओं को यूनिवर्सल सेंटर की इकाइयों के रूप में काम करना बुद्धिमानी होगी।

सुरक्षा के क्षेत्र में, एससीओ के पास काम के कई क्षेत्र हैं। सबसे पहले, यह दुनिया पर एक सभ्यता केंद्र के आधिपत्य को थोपने की मांग करने वाली ताकतों का मुकाबला करने के प्रयासों का समग्र समन्वय है। नए उपनिवेशवाद की इस नीति को एससीओ सदस्य राष्ट्रों सहित कई गैर-पश्चिमी राष्ट्रों के बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस अर्थ में, हमें संगठन को और विस्तारित करने की योजनाओं का स्वागत करना चाहिए-ईरान को एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए, अज़रबैजान गणराज्य और आर्मेनिया गणराज्य को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए, और मिस्र, कतर और सऊदी अरब को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए। साथ ही, संगठन के विस्तार पर विचार करते समय, एससीओ सदस्य देशों के दीर्घकालिक अच्छे पड़ोसी, मित्रता और सहयोग पर 2007 की संधि के अनुच्छेद 4 को सख्ती से ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसके अनुसार एससीओ सदस्यों को 'किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करना चाहिए जो अन्य अनुबंधित पक्षों के लिए शत्रुतापूर्ण है'[23]।

> 2021 में दुशांबे में बोलते हुए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस "अपने कर्मचारियों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार का मुकाबला करने में विशेषज्ञों को शामिल करके क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरएटीएस की कार्यात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी मानता है।

एससीओ और सीएसटीओ के बीच सुरक्षा कार्यों का समन्वय, संयुक्त बैठकें और कार्यक्रम महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी करीबी सहयोग की जरूरत है। अफगानिस्तान में स्थिति आज कुछ हद तक शांत है, लेकिन दुशांबे में एससीओ का घोषित लक्ष्य उस देश से उत्पन्न आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी और धार्मिक अतिवाद के खतरे को अवरुद्ध करते हुए एक समावेशी अंतर-अफगान शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देना अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है।

कोरोनावायरस महामारी ने सामान्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को काफी नुकसान पहुंचाया। महामारी के सामने, कई देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना चुना और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका में गिरावट आई। एससीओ देशों को भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शंघाई सहयोग संगठन में कोरोनोवायरस संक्रमण के प्रसार ने एक अत्यधिक जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान की स्थिति बनाई। इन स्थितियों में, सदस्य देशों को प्रतिबंधात्मक उपाय करने के लिए मजबूर किया गया था, जो उनके बीच व्यावहारिक सहयोग के कई पहलुओं के साथ-साथ प्रासंगिक मंत्रालयों, एजेंसियों और अन्य संरचनाओं के बीच संपर्कों की तीव्रता को प्रभावित नहीं कर सकता था।

इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, एक साथ काम करने के तरीकों को समायोजित करने का कार्य न केवल संरक्षित करने के लिए बल्कि महामारी की चुनौती के बावजूद बहुपक्षीय सहयोग को अतिरिक्त गति देने के लिए भी सामने आया है। और एससीओ ने धीरज की परीक्षा के बावजूद और उभरते जोखिमों और चुनौतियों का उचित जवाब देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौती को काफी हद तक पूरा किया है।

एससीओ महामारी के दौरान, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए परिचालन सहयोग में काफी अनुभव प्राप्त किया गया है और स्वच्छता और महामारी विज्ञान कल्याण और जैव सुरक्षा के क्षेत्र में गहरे सहयोग के लिए पूर्व शर्तें बनाई गई हैं। विदेश मंत्रियों, स्वच्छता और महामारी विज्ञान सेवाओं और पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठकों के साथ-साथ स्वास्थ्य, परिवहन और वित्त के क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श सहित कई गतिविधियां एससीओ के लिए एक नए ऑनलाइन मोड में चली गई हैं।

> एससीओ सहित केवल करीबी रूसी-चीनी सहयोग, यूरेशिया में सापेक्ष स्थिरता और विकास बनाए रख सकता है।

कुल मिलाकर, एससीओ सदस्य देशों ने उच्च स्तर की एकजुटता और आपसी समर्थन दिखाया है। जैसा कि एससीओ महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने दिसंबर 2020 में कहा था कि संगठन मुख्य क्षेत्रीय सहयोग तंत्र के काम को सुधारने और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों को विनियमित करने वाले दस्तावेजों का एक पारस्परिक सेट तैयार करने में कामयाब रहा है। इस अवधि का पहला हिस्सा रूसी राष्ट्रपति पद के दौरान गिर गया, जिसने इस सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई[24]।

नई स्थिति में कम महत्वपूर्ण एससीओ में रूस और चीन की भूमिका को सुदृढ़ करना नहीं है। दुनिया की उभरती द्विध्रुवीय संरचना में, वैश्विक आधिपत्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे अमेरिका और उसके

सहयोगियों का सामना न केवल रूस द्वारा किया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली चीन द्वारा भी किया जाता है। इन परिस्थितियों में, इन दोनों देशों के बीच सफल चर्चा के मामले में, सभी के लिए स्वीकार्य शर्तों पर एससीओ क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने और शांति बनाए रखने की संभावना बहुत अधिक है। एससीओ सहित केवल करीबी रूसी-चीनी सहयोग, यूरेशिया में सापेक्ष स्थिरता और विकास बनाए रख सकता है।

भारतीय वैश्विक परिषद

एससीओ राष्ट्रध्यक्ष परिषद - 2023

S E C U R E SCO

एक बहुआयामी रणनीति को आगे बढ़ाना

डिजिटल युग में नशीली दवाओं की तस्करी की चुनौतियों के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया

रहीमोव फरीदुन

यह शोध-पत्र शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दायरे में विशेष रूप से डिजिटल युग में नशीली दवाओं की तस्करी की उभरती चुनौती के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। चूंकि नशीली दवाओं का व्यापार तकनीकी प्रगति के अनुकूल है, इसलिए सीमा नियंत्रण और दंडात्मक उपायों जैसी पारंपरिक एंटी-नारकोटिक्स रणनीतियां अपर्याप्त साबित होती हैं। एक समग्र, बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, यह शोध-पत्र क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने, कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने, नीति और कानूनी सुधारों की वकालत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है। इसमें अग्रदूत रसायनों की निगरानी को आगे बढ़ाना, पूर्वानुमान प्रवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स को शामिल करना और अभिनव तकनीक को अपनाना शामिल है। अध्ययन में नशीली दवाओं के उपयोग और तस्करी के मूल कारणों को संबोधित करने पर जोर दिया गया है, जैसे कि गरीबी और असमानता, दंडात्मक रुख पर निवारक रुख की वकालत करते हुए। शोध-पत्र सभी एससीओ सदस्य राष्ट्रों और अन्य वैश्विक संगठनों से एक सहयोगी, निरंतर प्रयास का आग्रह करके समाप्त होता है, यह स्वीकार करते हुए कि केवल ऐसे प्रयासों के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी के विनाशकारी प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।

नशीली दवाओं की वैश्विक स्थिति का अवलोकन

अफगानिस्तान के विशाल अफीम के खेतों से लेकर दक्षिण अमेरिका के उपजाऊ कोका बागानों तक, वैश्विक दवा की स्थिति मानव प्रकृति, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक ड्राइवरों के परस्पर क्रिया से प्रभावित है। मनुष्य, किसी भी अन्य प्रजाति के विपरीत, अपने कार्यों के संभावित परिणामों को देखने की अनूठी क्षमता रखते हैं। इस क्षमता के बावजूद, इतिहास हमें सीमाओं को चुनौती देने की एक सम्मोहक प्रवृत्ति दिखाता है, अक्सर सीधे निषेधों का उल्लंघन करता है। यह मानवीय प्रवृत्ति भ्रष्टाचार और कर चोरी से लेकर शराब पीकर गाड़ी चलाने और ऋण दुरुपयोग तक व्यापक स्पेक्ट्रम में फैली हुई है। विशेष रूप से, यह मादक पदार्थों की तस्करी के दायरे में भी प्रमुखता से शामिल है, जो कठोर निषेधों के बावजूद, फलता-फूलता रहता है। अफगानिस्तान, लगातार गरीबी और सामाजिक असमानता से प्रेरित, हेरोइन के दुनिया के अग्रणी उत्पादक के रूप में उभरा है। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद 2021 में तालिबान की सत्ता में हालिया वापसी ने पानी को और खराब कर दिया है। अफीम की खेती पर औपचारिक प्रतिबंध के बावजूद, फसल का मूल्य बढ़ गया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और नशीली दवाओं की तस्करी में वृद्धि हुई है[25]।

> अफगानिस्तान, लगातार गरीबी और सामाजिक असमानता से प्रेरित, हेरोइन के दुनिया के अग्रणी उत्पादक के रूप में उभरा है। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद 2021 में तालिबान की सत्ता में हालिया वापसी ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

इसी तरह, लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से कोलंबिया, वैश्विक कोकीन व्यापार का केंद्र बन गया है। कोकीन का उत्पादन वहां पनपा है, इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि और ऐतिहासिक कारकों का लाभ उठाते हुए, जिसमें 1963 तक कोका की खेती की वैधता भी शामिल है। आज, कोलंबिया वैश्विक कोकीन बाजार पर एक महत्वपूर्ण पकड़ बनाए रखता है, जिससे अनुमानित वार्षिक राजस्व यूएस $ 100 बिलियन से अधिक हो जाता है[26]।

जैसे-जैसे हम वैश्विक नशीली दवाओं के व्यापार की जटिलताओं को देखते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि पारंपरिक काउंटर-रणनीतियां, मुख्य रूप से दंडात्मक उपायों और सीमा नियंत्रणों पर निर्भर हैं, कम हो रही हैं। इस निरंतर विकसित चुनौती का सामना करते हुए, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), अपनी विविध सदस्यता और व्यापक प्रभाव के साथ, नशीली दवाओं की तस्करी के मुद्दे का सामना करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है।

उत्पादन और परिवहन

नशीली दवाओं की तस्करी में जटिल नेटवर्क और विभिन्न परिवहन मार्ग शामिल हैं। अफगान हेरोइन ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और यूरोप के माध्यम से बाल्कन मार्ग सहित कई रास्तों का अनुसरण करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग गोल्डन ट्रायंगल[27] है, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन शामिल हैं। इस क्षेत्र ने हाल के वर्षों में क्रिस्टल मेथामफेटामाइन और मेथामफेटामाइन युक्त गोलियों के उत्पादन में वृद्धि देखी है। आपराधिक सिंडिकेट, जैसे कैंटन आपराधिक सुपर सिंडिकेट सैम गोर जिसे "द कंपनी" भी कहा जाता है, ने इस विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है[28]। अफगान हेरोइन का परिवहन म्यांमार से पड़ोसी देशों में मछली पकड़ने वाली छोटी नौकाओं, क्षेत्रों को पार करने वाले कारवां और बंदरगाह शहरों से शिपमेंट जैसे तरीकों पर निर्भर करता है।

> मुख्य रूप से दंडात्मक उपायों और सीमा नियंत्रणों पर निर्भर पारंपरिक जवाबी रणनीतियां कम पड़ रही हैं। इस निरंतर विकसित चुनौती का सामना करते हुए, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), अपनी विविध सदस्यता और व्यापक प्रभाव के साथ, नशीली दवाओं की तस्करी के मुद्दे का सामना करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है।

इसी तरह, लैटिन अमेरिकी कोकीन का परिवहन मुख्य रूप से कोलंबिया में शुरू होता है और रूस, मध्य एशियाई क्षेत्र और अन्य देशों सहित विभिन्न गंतव्यों को लक्षित करता है[29]। जोखिम को कम करने के लिए, कोकीन शिपमेंट को विभिन्न जहाजों पर लोड किए गए छोटे कार्गो में विभाजित किया जाता है। यूरोप पहुंचने के बाद, कोकीन को विभिन्न माध्यमों से ले जाया जाता है, जैसे कि ट्रक और रेल, कानून प्रवर्तन से बचने के लिए लगातार मार्गों और परिवहन के तरीकों को बदलते हैं। रूस और मध्य एशिया में

प्रवेश करने के लिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को पार किया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों के भीतर कोकीन का सफल वितरण सुनिश्चित होता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि नशीली दवाओं की तस्करी के संचालन में सीमा नियंत्रण को दूर करने और कानून प्रवर्तन से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियां शामिल हो सकती हैं। ये रणनीतियाँ अक्सर सीमा सुरक्षा में कमजोरियों का फायदा उठाती हैं, जिसमें तस्करी के तरीके शामिल हैं जो लगातार विकसित हो रहे हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हैं। इन रणनीतियों का सटीक विवरण अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आपराधिक सिंडिकेट पहचान और अवरोधन के जोखिमों को कम करते हुए अवैध पदार्थों के आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीति का उपयोग करते हैं[30]।

पारंपरिक मादक पदार्थों की तस्करी की जटिल चुनौती के बीच उभरना अवैध प्रयोगशालाओं का बढ़ता प्रचलन है। गुप्त रूप से काम करते हुए, परिष्कृत तकनीक से लैस ये प्रयोगशालाएं, बड़ी मात्रा में अवैध पदार्थों का निर्माण और वितरण करती हैं[31]। ये प्रयोगशालाएं छाया अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिससे सरकारों के लिए बहुमुखी खतरा पैदा होता है[32]।

इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने दवा उत्पादन के लिए क्लस्टर सिस्टम के भविष्य के विकास को सक्षम किया है। ऐसी प्रणालियों में रोबोट, रिमोट-नियंत्रित रिएक्टर शामिल हैं, जो मानव भागीदारी और जोखिम को काफी कम करते हैं। सिस्टम स्वायत्त रूप से कार्य करता है, जिसमें वाहक संबंधित कंटेनरों में विशिष्ट सामग्री जोड़ने का एक विलक्षण कार्य करते हैं। इस तरह के क्लस्टर रिएक्टर सिस्टम में बदलाव एक अतिरिक्त चुनौती है क्योंकि यह मानव श्रम की आवश्यकता को कम करता है और पता लगाना बेहद मुश्किल बनाता है। इस तरह की प्रणालियों को घरों, कारों या किसी भी स्थान पर अस्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है, जिससे पता लगाना एक असंभव घटना बन जाती है। नतीजतन, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लड़ाई एक नए युग में प्रवेश कर गई है जहां नवाचार और सतर्कता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है।

इन चुनौतियों के अलावा, अवैध पदार्थों के उत्पादन के निहितार्थ को काफी जोखिम और संभावित नुकसान को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाता है जो स्पष्ट कानूनी और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की जगह लेते हैं। मुनाफे की खोज में गुणवत्ता और सुरक्षा से अक्सर समझौता किया जाता है, जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। दवाओं की शुद्धता, उत्पादन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक, अक्सर महत्वपूर्ण गुणवत्ता के मुद्दों के कारण अनदेखा किया जाता है। उपयोग किए गए अग्रदूतों[33] की शुद्धता और उत्पादन के दौरान शुद्धिकरण और निस्पंदन विधियों की प्रभावशीलता जैसे कारकों को अक्सर अनुभवहीनता या लापरवाही के कारण अनदेखा किया जाता है। नतीजतन, ये भूमिगत संचालन उप-पदार्थों का उत्पादन और वितरण करते हैं, जिससे उपभोक्ता स्वास्थ्य को खतरा होता है। अपर्याप्त भंडारण और परिवहन स्थितियों के साथ मिलकर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों की यह अवहेलना, उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता कर सकती है, जिससे अंतिम उपभोक्ता के लिए और भी अधिक जोखिम पैदा हो सकता है।

आखिरकार, ये गुप्त प्रयोगशालाएं और उनके संबंधित नेटवर्क एक प्रणालीगत मुद्दा पेश करते हैं जो कानून का उल्लंघन करने से परे है; वे वित्तीय लाभ की खोज में नागरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को सक्रिय रूप से जोखिम में डालते हैं, उनकी पहचान और रोकथाम में बढ़ते प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

अवैध प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत चुनौतियों को संबोधित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। पूर्ववर्तियों पर इनमें से कई पदार्थों के वैध उपयोगों को देखते हुए[33], व्यापक प्रतिबंधों को लागू करना अनजाने में दवा और रासायनिक उद्योग को प्रभावित कर सकता है। मौत की सजा तक विस्तारित कठोर दंड, लाभप्रदता में वृद्धि के कारण उद्योग की अपील को बढ़ा सकता है, संभावित रूप से अवैध दवा व्यापार में सक्षम विशेषज्ञों को आकर्षित कर सकता है।

डिजिटल युग में कानून प्रवर्तन के लिए उभरती चुनौतियां

डार्कनेट इतना विकसित है कि उनके काम की दक्षता और सामान्य क्षमता के संदर्भ में, इस व्यवसाय में प्रतिभागी विशेष सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और नेटवर्क के बुनियादी संरचना की सुरक्षा की डिग्री और सूचना सुरक्षा के दृष्टिकोण के मामले में, वे रणनीतिक उद्देश्यों के कई राष्ट्र संस्थानों को पार करते हैं।

अनाम नेटवर्क (टोर और 12पी[34]) जैसी तकनीकी प्रगति का आगमन, वेब 3.0[35] का विकास, और अनाम भुगतान विधियां मामलों को और जटिल बनाती हैं। ये उपकरण नशीली दवाओं की तस्करी पर पारंपरिक राष्ट्र नियंत्रण को तेजी से अप्रभावी बनाने की धमकी देते हैं, और यह अनिश्चित है कि क्या इस चुनौती की भयावहता, और नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बढ़ते खतरे से समाज की रक्षा के लिए आवश्यक रणनीतिक उपायों को पूरी तरह से समझा जाता है।

ड्रग व्यापार की जटिलता का उदाहरण डार्कनेट मार्केटप्लेस पर वर्तमान बाजार के रुझानों से मिलता है, जो लोकप्रियता के विभिन्न स्तरों के साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पूरा करते हैं[36]।

मेफेड्रोन: मेफेड्रोन सबसे लोकप्रिय नशीली दवा है, जिसमें कुल सौदों का 32 प्रतिशत और औसत कीमत 22.50 अमेरिकी डॉलर प्रति ग्राम है। यह दवा, जिसे आयातित अग्रदूतों से देशों में सस्ते में उत्पादित किया जा सकता है, ने कोकीन, एमडीएमए, या मेथामफेटामाइन जैसे अन्य पदार्थों की तुलना में इसकी सामर्थ्य के कारण एक व्यापक ग्राहक आधार प्राप्त किया है। आर्थिक पहलू के अलावा, शरीर से अपेक्षाकृत तेजी से उन्मूलन और कथित सुरक्षा ने इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाइड्रा के पतन के बाद, बाजार ने घर के बने मेफेड्रोन की वृद्धि देखी, जिसमें अक्सर बीके-4 या एमडीपीएफ जैसी विषाक्त अशुद्धियां होती हैं, जो अधिकांश स्वास्थ्य मुद्दों और मेफेड्रोन के उपयोग से संबंधित मौतों से जुड़ी हुई हैं।

चरस: कुल सौदों में से 31 प्रतिशत के साथ हशीश लोकप्रियता के मामले में दूसरे स्थान पर है। इस दवा

की पहुंच और इसके साइकोएक्टिव गुण उपयोगकर्ताओं के बीच इसकी प्राथमिकता में योगदान करते हैं। प्रति ग्राम औसत कीमत 25.00 अमेरिकी डॉलर है। फिर भी, अति प्रयोग से मनोवैज्ञानिक निर्भरता और संज्ञानात्मक हानि हो सकती है।

भाँग: कुल सौदों का 19 प्रतिशत हिस्सा, कैनबिस अपने हल्के साइकोएक्टिव प्रभावों और व्यापक उपलब्धता के कारण एक और अच्छी तरह से पसंद की जाने वाली दवा है। हशीश की तरह, कैनबिस की भी औसत कीमत 25.00 अमेरिकी डॉलर प्रति ग्राम है। हालांकि, लगातार उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे चिंता और व्यामोह हो सकते हैं।

अल्फा-पीवीपी: इस नशीली दवा का कुल सौदों का 9 प्रतिशत है, जो अपने सुदृढ़ साइकोएक्टिव प्रभावों और कार्रवाई की लंबी अवधि के लिए जानी जाती है। अल्फा-पीवीपी के लिए प्रति ग्राम औसत मूल्य 27.50 अमेरिकी डॉलर है। अनुशंसित खुराक से अधिक मनोवैज्ञानिक स्थिति, नकारात्मक व्यवहार और यहां तक कि दिल की विफलता भी हो सकती है।

कोकेन: इसकी उच्च लागत (यूएस $ 112.50 प्रति ग्राम) और सौदों के तुलनात्मक रूप से कम प्रतिशत (5%) के बावजूद, कोकीन अपनी प्रतिष्ठा और रोमांच के कारण मांग में रहता है। उच्च खुराक से नियंत्रण, आक्रामक व्यवहार और दिल का दौरा और स्ट्रोक सहित गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का नुकसान हो सकता है।

एम्फ़ैटेमिन: लोकप्रियता में छठे स्थान पर, एम्फ़ैटेमिन भी 18.75 अमेरिकी डॉलर प्रति ग्राम की औसत कीमत के साथ कुल सौदों का 5 प्रतिशत बनाते हैं। "काम की दवा" के रूप में जाना जाता है, यह अपनी उत्तेजना और ऊर्जा प्रभाव में वृद्धि के लिए लोकप्रिय है। फिर भी, अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप मनोविकृति, अप्रत्याशित व्यवहार और मस्तिष्क समारोह को दीर्घकालिक क्षति हो सकती है। हालांकि, कठोर कानून प्रवर्तन कार्यों और अल्फा जैसी नई बाजार दवाओं के उदय के कारण एम्फ़ैटेमिन की लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है।

ये रैंकिंग दवा बाजार की बदलती गतिशीलता को उजागर करती है, जिसमें लोकप्रियता सामर्थ्य, प्रभाव, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन गतिविधियों जैसे कारकों से प्रभावित होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बदलाव और नए बाजारों के उद्भव ने इन पदार्थों की उपलब्धता और मांग को काफी प्रभावित किया है[37]।

अवैध नशीली दवाओं के व्यापार की पेचीदगियां, विशेष रूप से डार्कनेट मार्केटप्लेस की भूलभुलैया सीमाओं के भीतर, इसकी जटिलता को उजागर करती हैं। आपूर्तिकर्ताओं, मध्यस्थों और उपभोक्ताओं का एक विशाल नेटवर्क सहयोगी रूप से इस गूढ़ प्रणाली में संलग्न है, जो सभी डार्क वेब के छायादार घूंघट से छिपे हुए हैं। उच्च लाभप्रदता इस व्यापार को रेखांकित करती है, जिसमें कूरियर के लिए यूएस $ 800-9,600, वेबस्टोर ऑपरेटरों के लिए यूएस $ 1,280-1,600 अमेरिकी डॉलर की मासिक आय से लेकर कमाई, और यहां तक कि इन डार्कनेट दुकानों के मालिकों के लिए 50,000-60,000[38] अमेरिकी डॉलर तक की कमाई होती है[39]।

फिलहाल, घरेलू विशेष सेवाएं केवल सांपों से भरे एक जार को देख रही हैं और थोड़ा-थोड़ा करके किसी भी जानकारी को इकट्ठा कर रही हैं जो उन्हें किसी विशेष साइट के नेताओं के निशान तक ले जा सकती है, लेकिन जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, विशेष सेवाओं के लिए स्क्वीड के प्रमुख की तुलना में तम्बू से लड़ना अधिक लाभदायक और सुविधाजनक है। लुभावने रिटर्न के बावजूद, उद्योग खतरे से भरा हुआ है, अक्सर भ्रष्टाचार से उलझा हुआ है क्योंकि कार्टेल राजनीतिक और कानून प्रवर्तन हलकों में घुसने का प्रयास करते हैं, रिश्वतखोरी और धमकियों से ब्लैकमेल तक की रणनीतियों की एक सरणी का उपयोग करते हैं।

बिक्री के बिंदु पर जटिलता प्रतिभागियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को दर्शाती है, पारंपरिक स्ट्रीट डीलरों से लेकर गुप्त ऑनलाइन ऑपरेटरों तक। तकनीकी प्रगति ने भौतिक से ऑनलाइन मार्केटप्लेस में संक्रमण को प्रेरित किया है, जिससे दवा की कीमतों में एक सराहनीय मुद्रास्फीति हुई है। वर्तमान में, नशीली दवाओं साइबर अपराध की सीमा पर आपराधिक गतिविधि का एक क्षेत्र बन गया है। नतीजतन, आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमआईए) के गुप्त प्रभागों के विभाग इन अपराधों का मुकाबला करने में कार्यरत हैं। परिचालन और तकनीकी विभागों के कर्मचारी डीलरों की पहचान करने और साइबर हमलों, जैसे हैकिंग और डीडीओएस हमलों को रोकने के लिए कंप्यूटर और अन्य परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अपने काम के घंटे बिताते हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में उनकी सफलता ज्ञान, धन और तकनीकी क्षमताओं की कमी से सीमित है।

> तकनीकी प्रगति ने भौतिक से ऑनलाइन मार्केटप्लेस में संक्रमण को प्रेरित किया है, जिससे दवा की कीमतों में एक सराहनीय मुद्रास्फीति हुई है। वर्तमान में, नशीली दवाओं साइबर अपराध की सीमा पर आपराधिक गतिविधि का एक क्षेत्र बन गया है।

व्यापार का विकास अब उपभोक्ताओं को इन प्लेटफार्मों पर डीलरों के साथ सीधे चर्चा करते हुए देखता है, अप्राप्य क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान करता है और निर्दिष्ट वितरण स्थानों पर सामान प्राप्त करता है। यह कायापलट उन बाधाओं को रेखांकित करता है जो अधिकारियों को इस गुप्त वाणिज्य को दबाने में सामना करना पड़ता है।

निर्णय लेने वालों द्वारा सामना की जाने वाली यह दुविधा शतरंज में "ज़ुगज़वांग" स्थिति के समान है, जहां कोई भी कदम स्थिति को खराब करता है[40]। यह दुर्दशा महत्वपूर्ण सवाल उठाती है: क्या अधिकारी समस्या के पैमाने और आसन्न खतरे को पूरी तरह से समझते हैं? यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे वास्तव में इस चुनौती की भयावहता और समाज को नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के तेज संकट से बचाने के लिए आवश्यक रणनीतिक उपायों को समझते हैं। कानून प्रवर्तन द्वारा सामना की जाने वाली चुनौती प्राचीन हाइड्रा मिथक के समान है: एक अवैध साइट को बंद कर दें और इसके स्थान पर तीन और दिखाई दें। एक बार गठित होने के बाद, दवा बाजार राष्ट्र के अभिजात वर्ग के भीतर के तत्वों के संरक्षण से सुदृढ़ होता है। यह एक शाश्वत समस्या में बदल जाता है जिसमें एक निश्चित समाधान की कमी लगती है।

ड्रग ट्रैफिकिंग चुनौती के लिए बहुआयामी प्रतिक्रिया तेज करना

बाजार की गतिशीलता, प्रतिभागियों और दवा वरीयताओं सहित दवा व्यापार के जटिल विवरणों को समझना, प्रभावी काउंटर रणनीतियों को विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। नशीली दवाओं के व्यापार के विकास और डिजिटल प्लेटफार्मों पर इसके प्रवास को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के पारंपरिक तरीके, जैसे कि विशुद्ध रूप से दंडात्मक उपाय और सीमा नियंत्रण रणनीतियां, अब पर्याप्त नहीं हो सकती हैं।

> एससीओ की अपनी विविध सदस्यता और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अनूठी स्थिति है। एससीओ क्षेत्र के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए, हमें एक समग्र दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता है जो रणनीति की एक विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करता है-क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने, कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने, नीति और कानूनी सुधारों की वकालत करने से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देने तक।

एससीओ की अपनी विविध सदस्यता और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अनूठी स्थिति है। एससीओ क्षेत्र के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए, हमें एक समग्र दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता है जो रणनीति की एक विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करता है-क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने, कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने, नीति और कानूनी सुधारों की वकालत करने से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देने तक।

क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना:[41] नशीली दवाओं की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से लड़ने में एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। खुफिया जानकारी साझा करना, कानूनी संरचना और प्रक्रियाओं का सामंजस्य, और संयुक्त अभियान नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क को बाधित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

कानून प्रवर्तन क्षमताओं में वृद्धि: जैसे-जैसे ड्रग व्यापार डिजिटल क्षेत्र में जाता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस नई सीमा को नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस होना चाहिए। इसका मतलब साइबर अपराध जांच, डिजिटल फोरेंसिक और कानून प्रवर्तन में उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण में निवेश करना है।

नीति और कानूनी सुधारों की वकालत: नशीली दवाओं के व्यापार के मांग पक्ष को संबोधित करने के लिए दंडात्मक से निवारक उपायों में बदलाव की आवश्यकता होती है। इसमें नीतिगत सुधार शामिल हैं जो

सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में दवा के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि नुकसान में कमी की रणनीति और दवा उपचार कार्यक्रम।

सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देना: ओवरडोज की रोकथाम, नुकसान में कमी और दवा निर्भरता उपचार सहित दवा उपयोगकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अवैध दवाओं की मांग को कम करने में योगदान कर सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़े जोखिमों और अवैध पदार्थों के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी शामिल हैं।

परिसंचरण में पदार्थों की विविधता को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत दवाओं द्वारा उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अल्फा-पीवीपी लोकप्रियता में वृद्धि को संबोधित करने में न केवल कानून प्रवर्तन कार्रवाई शामिल है, बल्कि इसकी मांग को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप भी शामिल हैं। इस तरह के उपायों को लागू करके, हम ओवरडोज से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना शुरू कर सकते हैं, बाजार को हल्की दवाओं की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं, और पर्याप्त उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।

दवा निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अग्रदूत रसायनों की निगरानी और नियंत्रण को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे पदार्थों की बिक्री की निगरानी और विनियमन के लिए विनियम और नियंत्रण तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, विशेषकर जब उनके पास वैध औद्योगिक उपयोग होते हैं, ताकि अवैध दवा उत्पादन के लिए उनके विचलन को रोका जा सके। सरकारों और दवा उद्योग को अभिनव समाधान तैयार करने के लिए सहयोग करना चाहिए, उदाहरण के लिए, ऐसे अग्रदूतों को उनके वैध उपयोग को बाधित किए बिना, अवैध प्रयोगशालाओं के लिए कम वांछनीय या उपयोगी बना सकते हैं।

> कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग भी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारी हो सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषिकी का उपयोग भी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारी हो सकता है। प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग पैटर्न की पहचान करने और अपराध दर, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और स्थानीय नशीली दवाओं के उपयोग के रुझानों जैसे कारकों के आधार पर नए नशीली दवाओं की तस्करी मार्गों या प्रयोगशालाओं के संभावित उद्भव का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है[42]। एआई का लाभ ऑनलाइन ड्रग तस्करी गतिविधियों की पहचान में भी उठाया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल फुटप्रिंट[43] और डार्क वेब पर लेनदेन पैटर्न के विश्लेषण के माध्यम से।

इसके अतिरिक्त, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में अभिनव प्रौद्योगिकी का एकीकरण परिवर्तनकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग, सभी लेनदेन और संचार का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड

प्रदान कर सकता है, जिससे अपराधियों के लिए अपने ट्रैक को कवर करना कठिन हो जाता है। संभावित मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों की निगरानी और अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और उन्नत निगरानी उपकरण तैनात किए जा सकते हैं।

इन सबसे ऊपर, नशीली दवाओं के उपयोग और तस्करी के मूल कारणों को संबोधित करना-गरीबी, असमानता, अवसर की कमी-किसी भी प्रभावी रणनीति का एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए। एक स्थायी समाधान के लिए उन लोगों को व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता होगी जो अन्यथा दवा व्यापार में आकर्षित हो सकते हैं, चाहे अन्य विकल्पों की कमी के माध्यम से या कठिन परिस्थितियों से निपटने के साधन के रूप में। इसमें शिक्षा और रोजगार सृजन से लेकर सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और सामाजिक गतिशीलता के अवसरों तक कई उपाय शामिल होंगे।

अंत में, वैश्विक दवा व्यापार एक तेजी से जटिल, बहुआयामी चुनौती बनने के लिए विकसित हुआ है। इसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसी तरह की सूक्ष्म और बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। जबकि कानून प्रवर्तन और दंडात्मक उपायों की भूमिका है, हमें रोकथाम और हस्तक्षेप रणनीतियों की आवश्यकता को भी पहचानना चाहिए जो नशीली दवाओं के उपयोग और तस्करी के सामाजिक और आर्थिक मूल कारणों को संबोधित करते हैं। इस संबंध में, शंघाई सहयोग संगठन, और वास्तव में सभी देशों और संगठनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह केवल एक व्यापक, सहकारी और निरंतर प्रयास के माध्यम से है कि हम इस वैश्विक संकट के विनाशकारी प्रभाव को कम करने की आशा कर सकते हैं।

- अटलांटिक काउंसिल। "तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान का ड्रग व्यापार फलफूल रहा है। दक्षिण एशिया स्रोत: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/afghani- stans-drug-trade-is-booming-under-taliban-rule/ से पुनः प्राप्त

- ऑस्ट्रेलियाई आपराधिक खुफिया आयोग। "अवैध ड्रग डेटा रिपोर्ट 2015-16: गुप्त लेबरेटो-रीस और अग्रदूत।: https://www.acic.gov.au/sites/default/files/2020-08/iddr_2015-16_clandestine_laboratories_and_precursors.pdf से पुनः प्राप्त

- Darknet.org.uk। "वेब 3.0 और डार्कनेट के गोपनीयता निहितार्थ: https://www.darknet. org.uk/2023/03/privacy-implications-of-web-3-0-and-darknets/ से पुनः प्राप्त

- I2P. https://geti2p.com/en/ से पुनः प्राप्त

- INCB. "अग्रदूतों की लाल सूची 2020।: ttps://www.incb.org/documents/PRECURSORS/RED_LIST/2020/Red_List_2020_E.pdf से पुनः प्राप्त

- पलांतिर।: https://www.palantir.com/index.html से पुनः प्राप्त

- ScienceDirect. "ड्रग शुद्धता।: https://www.sciencedirect.com/topics/nurs- ing-and-health-professions/drug-purity से पुनः प्राप्त

- ScienceDirect. "डार्क वेब की खोज: क्रिप्टोमार्केट लेनदेन में भाषाई पैटर्न का एक पूर्वव्यापी विश्लेषण: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300216 से पुनः प्राप्त

- ScienceDirect. "गोपनीयता, सुरक्षा और विश्वास के संदर्भ में क्रिप्टोमार्केट का भविष्य: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2666281720303954 से पुनः प्राप्त

- स्प्रिंगर लिंक। "डार्कनेट पर नशीली दवाओं बेचना: ड्रग क्रिप्टोमार्केट्स की एक टाइपोलॉजी।: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10610-016-9329-7.pdf से पुनः प्राप्त

- मादक द्रव्यों के सेवन की नीति। "अवैध दवा आपूर्ति नेटवर्क को समझना: अंतर-राष्ट्रीय साक्ष्य की एक व्यवस्थित समीक्षा।: https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/ s13011-021-00375-w से पुनः प्राप्त

- स्वानसी विश्वविद्यालय। "डार्क नेट ड्रग मार्केट का उदय और चुनौती। से पुनः प्राप्त: https://www.swansea.ac.uk/media/The-Rise-and-Challenge-of-Dark-Net-Drug-Markets.pdf

- चर्चा। "डार्कनेट मार्केट चोरी किए गए व्यक्तिगत डेटा को बेचकर राजस्व में लाखों उत्पन्न करता है: आपूर्ति

श्रृंखला अध्ययन पाता है।: https://theconversation.com/darknet-markets-generate-mil-lions-in-revenue-selling-stolen-personal-data-supply-chain-study-finds-193506 से पुनः प्राप्त

- चर्चा। "डार्कनेट मार्केट चोरी किए गए व्यक्तिगत डेटा को बेचकर राजस्व में लाखों उत्पन्न करता है: आपूर्ति श्रृंखला अध्ययन पाता है।: https://theconversation.com/darknet-markets-generate-mil-lions-in-revenue-selling-stolen-personal-data-supply-chain-study-finds-193506 से पुनः प्राप्त
- टीआरटी दुनिया। "युद्ध के दशकों के बाद, अफगानिस्तान का ड्रग व्यापार पहले कभी नहीं बढ़ा। टीआरटी वर्ल्ड मैग-एज़िन।: https://www.trtworld.com/magazine/after-decades-of-war-afghanistan-s-drug- trade-booms-like-never-before-46284 से पुनः प्राप्त
- यूएनओडीसी। “Announcing the Launch of the Livelihoods, Security, and Service Programme (LSS).” Retrieved from यूएनओडीसी। "आजीविका, सुरक्षा और सेवा कार्यक्रम (एलएसएस) के शुभारंभ की घोषणा। से पुनः प्राप्त: https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/4349a4ee-cac4-440e-9d39-d2c21869e49a
- यूएनओडीसी। "ग्लोबल कोकीन रिपोर्ट 2023।: https://www.unodc.org/documents/da- ta-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf से पुनः प्राप्त
- यूएनओडीसी। "ग्लोबल कोकीन रिपोर्ट 2023।: https://www.unodc.org/documents/da- ta-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf से पुनः प्राप्त
- यूएनओडीसी। "2021 में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में जब्त किए गए एक बिलियन से अधिक मेथामफेटामाइन टैबलेट क्योंकि क्षेत्रीय ड्रग व्यापार का विस्तार जारी है।: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2022/June/unodc-report_-over-one-billion-methamphetamine-tablets-seized-in-east-and- southeast-asia-in-2021-as-the-regional-drug-trade-continues-to-expand.html से पुनः प्राप्त
- यूएनओडीसी। "वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021: गुप्त प्रयोगशालाओं का पता लगाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया।: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2021/9.1_Clandestine_laboratories_detect-ed_and_dismantled.pdf से पुनः प्राप्त
- "पकड़ा गया, और फिर गॉडफादर: सैम गोर, एशिया भर में एक विशाल ड्रग डीलिंग।: https://www.world-today-news.com/caught-and-then-the-godfather-sam-gore-a-gi- ant-drug-dealing-across-asia/ से पुनः प्राप्त

भारतीय वैश्विक परिषद

एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद - 2023

SECURE SCO

एससीओ में क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को सुदृढ़ करना

दावलतोव कामरोनबेक

संजरबेक अग्ली

पृष्ठभूमि

आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में संयोजकता एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), जिसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और लोगों के आदान-प्रदान के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में संयोजकता के महत्व को पहचानता है। यह शोध-पत्र एससीओ संरचना के भीतर क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता दोनों को सुदृढ़ करने के महत्व की पड़ताल करता है। यह क्षेत्र में संयोजकता की वर्तमान स्थिति की जांच करता है, बुनियादी संरचना के विकास, डिजिटल संयोजकता और नीति समन्वय सहित चुनौतियों, संयोजकता की पहचान करता है।

प्रस्तावना

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में एक विशाल भौगोलिक विस्तार और विविध सदस्यता, चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान और चार मध्य एशियाई राष्ट्र (इस वर्ष से ईरान) शामिल हैं, जो संयोजकता को क्षेत्रीय विकास और सहयोग का एक महत्वपूर्ण साधन बनाते हैं।

आज, एससीओ 34 मिलियन किमी 2 से अधिक को कवर करता है (यह यूरेशियन महाद्वीप के भूभाग का 60% से अधिक है)। एससीओ देशों की कुल आबादी 3.2 अरब से अधिक है, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी के बराबर है। गौरतलब है कि अकेले भारत की आबादी 1.425 अरब (2023) है, और चीन की 1.411 अरब (2023)[44] है।

तीन देशों को एससीओ पर्यवेक्षक राष्ट्रों का दर्जा प्राप्त है-इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, बेलारूस गणराज्य और मंगोलिया गणराज्य।

छह देश एससीओ संवाद साझेदार हैं-आर्मेनिया गणराज्य, अजरबैजान गणराज्य, कंबोडिया साम्राज्य, नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, तुर्की गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य।

जैसे-जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, एससीओ क्षेत्र के भीतर संयोजकता बढ़ाना एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में उभरा है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य एससीओ के क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग में संयोजकता की भूमिका का पता लगाना और इसके भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर चर्चा करना है।

एससीओ सबसे पहले, यह एससीओ क्षेत्र के भीतर संयोजकता की वर्तमान स्थिति का अवलोकन प्रदान करना चाहता है, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल संयोजकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों, चुनौतियों और अंतराल को उजागर करता है। दूसरा, इस शोध-पत्र का उद्देश्य उन उपायों और पहलों का पता लगाना है जो एससीओ के भीतर क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को सुदृढ़ कर सकते हैं। यह परिवहन बुनियादी संरचना को बढ़ाने, मल्टीमॉडल परिवहन गलियारों को विकसित करने, व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को

सुव्यवस्थित करने की क्षमता की जांच करेगा।

इन प्रमुख पहलुओं की खोज करके, इस शोध-पत्र का उद्देश्य संयोजकता के लेंस के माध्यम से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एससीओ की भूमिका की समझ में योगदान करना है। यह एससीओ क्षेत्र के भीतर संयोजकता बढ़ाने के लिए अवसरों, चुनौतियों और संभावित भविष्य के प्रक्षेपवक्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना चाहता है। अंततः, एक सुदृढ़ और अधिक एकीकृत एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और आपसी सहयोग में योगदान देगा।

क्षेत्रीय संयोजकता

भले ही अफगानिस्तान एससीओ में केवल एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है, फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शुरू में एससीओ अस्थिर अफगानिस्तान से उत्पन्न क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संभावित खतरों से निपटने के इरादे से बनाया गया था। इस प्रकार, यह कारक संगठन के क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय सदस्यों की संयोजकता के मूलभूत पहलू में से एक है।

एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मंच के अलावा, यह अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति और क्षेत्र में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाली केन्द्रापसारक ताकतों पर विचार करने के लिए एक वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच भी है, जो न केवल उजबेकिस्तान और भारत की सुरक्षा और विकास के लिए खतरा है, बल्कि एससीओ के सभी सदस्यों के लिए भी खतरा है। बुनियादी संरचना द्वारा प्रदान की गई भौतिक संयोजकता के अलावा, एससीओ मंच उन देशों के सरकारी अधिकारियों को एक साथ आने, चर्चा करने और अपने दृष्टिकोण साझा करने की अनुमति देता है जिनके पास व्यापक संबंध नहीं हो सकते हैं। यह क्षेत्र की स्थिरता में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, 2021 की एससीओ बैठक के दौरान, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों ने भेंट की और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से संबंधित द्विपक्षीय समझौतों के संबंध में अपनी चिंताओं पर चर्चा की। इसी तरह, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने पर्यटन, रेलवे, सैन्य विशेषज्ञता और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की पुन: पुष्टि करते हुए चर्चा की।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता काफी लंबे समय से एससीओ के एजेंडे में शामिल है। उदाहरण के लिए, 2018 के एससीओ शिखर सम्मेलन में, भारतीय प्रधानमंत्री ने यूरेशिया के 'सुरक्षित' होने के मूलभूत आयाम को स्पष्ट किया था। SECURE शब्द के अक्षर हैं:

S - हमारे नागरिकों की **सुरक्षा**,

E - सभी के लिए **आर्थिक** विकास,

C - क्षेत्र को **जोड़ना**,

U - हमारे लोगों को **एकजुट** करना,

R - संप्रभुता और अखंडता के लिए **सम्मान**, और

E - **पर्यावरण** संरक्षण[45]

बदले में, 15-16 जुलाई 2021 को, ताशकंद ने एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "मध्य और दक्षिण एशिया: क्षेत्रीय संयोजकता" की मेजबानी की। चुनौतियां और अवसर". उज़्बेकिस्तान द्वारा शुरू किए गए मंच ने 40 देशों के उच्च रैंकिंग अधिकारियों के साथ-साथ प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधिमंडलों को एक साथ लाया[46]।

> जैसा कि राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने 12 जनवरी, 2023 को "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ" शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में उल्लेख किया था, उजबेकिस्तान "उत्तर-दक्षिण" अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के विकास का पूरी तरह से समर्थन करता है, जो यूरेशियन क्षेत्र में अग्रणी परिवहन धमनियों में से एक है और भारत द्वारा भी बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अलावा, उज्बेकिस्तान में 17 सितंबर, 2022 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों के 22वें शिखर सम्मेलन में, राष्ट्रों के प्रमुखों ने 28 विभिन्न निर्णयों और समझौतों को मंज़ूरी दी है। ये निर्णय दीर्घकालिक अच्छे पड़ोसी, मित्रता और सहयोग पर संधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 2023-2027 के लिए व्यापक कार्य योजना से संबंधित हैं, ताकि इंटरकनेक्टिविटी विकसित की जा सके और कुशल परिवहन गलियारों का निर्माण किया जा सके[47]।

ये तथ्य और उपाय संयोजकता और एकता में एससीओ सदस्य राष्ट्रों की रुचि के बारे में वक्तव्य की स्पष्ट पुष्टि हो सकते हैं।

परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग, क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परिवहन नेटवर्क

लगभग सभी सदस्य राष्ट्रों ने सड़क, रेल और हवाई परिवहन नेटवर्क के निर्माण और सुधार में निवेश किया है, जिससे माल, सेवाओं और लोगों की आवाजाही की सुविधा मिलती है।

चीन-किर्गिस्तान-उजबेकिस्तान रेलवे जैसे प्रमुख परिवहन गलियारों के पूरा होने से इस क्षेत्र के भीतर संयोजकता में काफी सुधार हुआ है। इन पहलों से न केवल व्यापार और आर्थिक आदान-प्रदान में वृद्धि हुई है, बल्कि लोगों के बीच संपर्क भी सुदृढ़ हुआ है।

भारत हिंद महासागर में समुद्री लेन के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। इस क्रम में, ट्रांस-अफगान रेलवे परियोजना के माध्यम से मध्य और दक्षिण एशिया की संयोजकता को सुदृढ़ करना वैश्विक रसद और मूल्य श्रृंखलाओं में योगदान देता है। यह यूरेशियन क्षेत्र और उसके पड़ोसी देशों दोनों के लाभ की सेवा करता है।

जैसा कि राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने 12 जनवरी, 2023 को "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ" शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में उल्लेख किया है, उजबेकिस्तान "उत्तर-दक्षिण" अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के विकास का पूरी तरह से समर्थन करता है, जो यूरेशियन क्षेत्र में अग्रणी परिवहन धमनियों में से एक है और भारत द्वारा भी बढ़ावा दिया गया है[48]।

एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में अपने भाषण में उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने परिवहन और पारगमन क्षमता के व्यापक उपयोग, व्यापार और आर्थिक संबंधों को तेज करने के लिए संगठन के सदस्य देशों के परिवहन संपर्क के विकास, औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने के महत्व पर जोर दिया और इस दिशा में कई पहलों की घोषणा की[49]।

एससीओ अंतरिक्ष में परिवहन संयोजकता के विस्तार के मुद्दों पर उजबेकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख का इतना करीबी ध्यान आकस्मिक नहीं है। हमारा राष्ट्र, भागीदारों के साथ, विशाल एससीओ अंतरिक्ष की भौगोलिक विशेषताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहता है, जब देश पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच मुख्य कनेक्टिंग लिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

इसे अलग तरीके से रखने के लिए, यह क्षेत्र एक पुल जैसा दिखता है जो एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों के विस्तार के लिए असाधारण अवसर प्रस्तुत करता है। यह उन राष्ट्रों के तालमेल में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है जो संगठन के सदस्य हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में एससीओ देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने में सकारात्मक रुझान हैं। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर, राजनीतिक विश्वास और आपसी समझ स्थापित की गई है, चर्चा के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिकोण की समानता है और देशों और लोगों को एक साथ लाने की इच्छा है। यह सब एससीओ अंतरिक्ष में नए अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों के गठन के माध्यम से परिवहन संयोजकता को सुदृढ़ करने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाता है।

> संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर, राजनीतिक विश्वास और आपसी समझ स्थापित की गई है, चर्चा के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिकोण की समानता है और देशों और लोगों को एक साथ लाने की इच्छा है। यह सब एससीओ अंतरिक्ष में नए अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों के गठन के माध्यम से परिवहन संयोजकता को सुदृढ़ करने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाता है।

प्रतिवर्ष एससीओ के सदस्य देशों के परिवहन मंत्रियों की एक बैठक सदस्य देशों में से एक में आयोजित की जाती है। उदाहरण के लिए, 12 मई 2022 को, उजबेकिस्तान गणराज्य के खीवा में परिवहन मंत्रियों की नौवीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता उजबेकिस्तान ने की थी[50] और, 28 अप्रैल 2023 को, परिवहन मंत्रियों की दसवीं एससीओ मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली, भारत गणराज्य में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत गणराज्य के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी[51] ने की थी। ये बैठकें एससीओ सदस्य देशों की परिवहन नीति को तेज करने और निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इसके अलावा, भारत चाबहार के ईरानी बंदरगाह का उपयोग करने के विचार को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "मध्य और दक्षिण एशिया: क्षेत्रीय संयोजकता" में अपने भाषण में। चुनौतियां और अवसर" (15-16 जुलाई 2021, ताशकंद), भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्रीय संयोजकता में चाबहार के ईरानी बंदरगाह की व्यापक भागीदारी के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'हमने चाबहार बंदरगाह को आईएनएसटीसी के संरचना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत-उज्बेकिस्तान-ईरान-अफगानिस्तान चतुष्कोणीय कार्य समूह का गठन एक स्वागत योग्य विकास है[52]। आशा की जा रही है कि संगठन में ईरान (इस साल) के शामिल होने से इन संभावनाओं में जान आएगी।

भविष्य में, पर्यवेक्षक की स्थिति वाले राष्ट्रों के साथ-साथ संवाद भागीदारों की कीमत पर शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण प्रतिभागियों की संख्या में और वृद्धि, परिवहन और पारगमन क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लगातार विकास और कार्यान्वयन की अनुमति देगी। यह सब एससीओ के संरचना के भीतर परिवहन चर्चा की प्रकृति पर एक निश्चित पुनर्विचार की आवश्यकता है, इसके रणनीतिक प्रतिमान को अद्यतन करना और नए आशाजनक क्षेत्रों में प्रवेश करना।

ऊर्जा सहयोग

ऊर्जा संयोजकता एससीओ के भीतर क्षेत्रीय एकीकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सदस्य देशों ने ऊर्जा सहयोग के महत्व को स्वीकार किया है और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों

में कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए, मध्य एशिया-चीन गैस पाइपलाइन ने मध्य एशियाई देशों और चीन के बीच ऊर्जा संयोजकता को सुदृढ़ किया है, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में योगदान दिया है। इसके अलावा, पवन और सौर खेतों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में एससीओ के भीतर ऊर्जा संयोजकता और स्थिरता को और बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, सीमा पार ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने और सदस्य राष्ट्रों के बीच ऊर्जा नीतियों को सुसंगत बनाने के संदर्भ में सुधार के लिए जगह है।

कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान जैसे मध्य एशिया के देश, जो अपने प्रचुर हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए जाने जाते हैं, पाकिस्तान और भारत के लिए सुलभ ऊर्जा बाजारों के रूप में उभरे हैं। दक्षिण एशिया के इन दो देशों को महत्वपूर्ण ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधन उनके लिए विशेष रूप से मूल्यवान हो जाते हैं।

दूसरे शब्दों में, आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देने पर एससीओ का जोर, शायद, यूरेशिया तक भारत की पहुंच को रोक सकता है, और तापी और सीएएसरेम जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकता है जो ऊर्जा समृद्ध और ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्र के बीच की खाई को पाटना चाहते हैं[51]।

उल्लेखनीय है कि भारत अपनी हाइड्रोकार्बन आवश्यकताओं का करीब 80 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से अधिकांश पश्चिम एशियाई क्षेत्र से आयात करता है। इसने भारत को संसाधन समृद्ध मध्य एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा की तलाश करने और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तंत्रों के माध्यम से अपने व्यापार और परिवहन संबंधों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है[53]।

डिजिटल संयोजकता

डिजिटल परिवर्तन के युग में, डिजिटल संयोजकता क्षेत्रीय एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर रही है। एससीओ के सदस्य देशों ने डिजिटल संयोजकता के महत्व को पहचाना है और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। ब्रॉडबैंड संयोजकता में सुधार, इंटरनेट एक्सेस का विस्तार करने और क्षेत्र के भीतर ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यापार और सहयोग की सुविधा के लिए एससीओ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी पहल शुरू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य ई-कॉमर्स गतिविधियों, डिजिटल संयोजकता और सदस्य राष्ट्रों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है[54]।

एससीओ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सीमा पार ई-कॉमर्स गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एससीओ क्षेत्र के भीतर व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए एक समर्पित ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में काम करना चाहता है। यह व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जबकि उपभोक्ताओं को आसानी से ऑनलाइन खरीदारी करने में भी सक्षम बनाता है।

> आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देने पर एससीओ का जोर, शायद, यूरेशिया तक भारत की पहुंच को रोक सकता है, और तापी और कासारेम जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकता है जो ऊर्जा समृद्ध और ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्र के बीच की खाई को पाटना चाहते हैं।

एससीओ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहल एससीओ के सदस्य देशों के बीच डिजिटल व्यापार, सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में योगदान देती है, अंततः डिजिटल युग में क्षेत्रीय विकास और सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।

तीन बुराइयां

एससीओ के भीतर क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए व्यापार सुविधा उपायों को बढ़ावा देना आवश्यक है। सदस्य देशों को सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और व्यापार नियमों को सुसंगत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने से सीमा पार व्यापार की दक्षता में काफी सुधार हो सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना सीमा शुल्क, रसद और नियामक प्रक्रियाओं को एकीकृत और स्वचालित करके व्यापार सुविधा को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने और पारस्परिक मान्यता समझौतों को लागू करने से व्यापार प्रवाह में तेजी लाने और निर्बाध संयोजकता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

मध्य और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र में व्यापार, संयोजकता और विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता रखता है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक निकटता व्यापार, बुनियादी संरचना, ऊर्जा, पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है।

मध्य एशिया-दक्षिण एशिया (CASA) 1000 परियोजना जैसी क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से मध्य और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच बिजली व्यापार के लिए बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त, तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस पाइपलाइन परियोजना ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने और मध्य एशिया से दक्षिण एशिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का प्रयास करती है[55]।

आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार बाधाओं को कम करने जैसे व्यापार सुविधा उपायों का पता लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और मध्य एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (CAREC),

व्यापार, निवेश और परिवहन जैसे क्षेत्रों में चर्चा और सहयोग के लिए मंच प्रदान करते हैं।

मध्य और दक्षिण एशिया के बीच माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क, रेल और हवाई लिंक के विकास के साथ परिवहन और संयोजकता बुनियादी संरचना को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण फोकस है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और ईरान में चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जो चारों ओर से जमीन से घिरे मध्य एशियाई देशों के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान कर सकती हैं।

पिछले दशकों में, परिवहन गलियारों के कारण मध्य और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक सहयोग तेज हो गया है। उदाहरण के लिए, यदि 2017 में, उजबेकिस्तान और भारत के बीच व्यापार कारोबार 323.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, तो 2021 में, यह 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, उजबेकिस्तान और भारत के बीच कुल व्यापार की मात्रा 202214 में लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई[56]।

उजबेकिस्तान भारतीय निवेश के लिए खुला है और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके रासायनिक वस्तुओं, आईसीटी, फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं, वस्त्र और अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में सहयोग का स्वागत करता है। बदले में, उजबेकिस्तान में भारतीय निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है, और इन दिशाओं में सुदृढ़ सहयोग स्थापित किया गया है।

वर्तमान में, उजबेकिस्तान में भारतीय पूंजी की भागीदारी के साथ लगभग 400 उद्यम हैं। उज़्बेक-इंडिया ट्रेड हाउस नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, और उज़्बेकिस्तान-भारत उद्यमिता विकास केंद्र ताशकंद 15 में खोला गया था[57]।

इस बीच, उजबेकिस्तान और भारत (सामान्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया) के बीच सीधे जमीनी संचार की अनुपस्थिति के कारण, देश अपने कुल व्यापार और आर्थिक क्षमता का एहसास नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, उजबेकिस्तान और भारत परिवहन समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं और परिवहन और संचार इंटरकनेक्टिविटी विकसित करने का इरादा रखते हैं।

चुनौतियों पर काबू पाना

जबकि एससीओ के भीतर क्षेत्रीय संयोजकता बढ़ाने में प्रगति हुई है, कई चुनौतियां और अंतराल हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। सदस्य राष्ट्रों के बीच बुनियादी ढांचा असमानताएं मौजूद हैं, कुछ देशों में दूसरों की तुलना में अधिक विकसित परिवहन नेटवर्क हैं। बुनियादी संरचना के विकास में यह असंतुलन सुचारू संयोजकता में बाधा डाल सकता है और आर्थिक एकीकरण की पूरी क्षमता को सीमित कर सकता है। इसके अलावा, नियामक विसंगतियां और मानकों में अंतर वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध सीमा पार आवागमन के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निकट समन्वय, नीतिगत सामंजस्य और बुनियादी संरचना के विकास में निवेश की आवश्यकता है ताकि अंतराल को

पाटा जा सके और एससीओ क्षेत्र में समान संयोजकता सुनिश्चित की जा सके।

> अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देने में एससीओ के प्रयास अपने प्रभाव का विस्तार करने और अन्य क्षेत्रीय संगठनों और पहलों के साथ तालमेल बनाने के लिए आवश्यक हैं।

दक्षिण और मध्य एशिया के बीच एकीकरण की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में बनी हुई है, जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में संघर्षों और सीमा विवादों के कारण है।

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, पाकिस्तान पांचवें स्थान पर है, और बांग्लादेश सातवें स्थान पर है, दक्षिण एशिया बाजार अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण बुनियादी संरचना के विकास और क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संबंधों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस संबंध में, पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अध्येता यह भी सुझाव देता है कि दो पड़ोसी क्षेत्रों के देश जलवायु के मामले में परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्र मुख्य रूप से बढ़ते तापमान और पानी की कमी से पीड़ित हैं।

उज़्बेकिस्तान, अन्य सभी मध्य एशियाई देशों की तरह, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का सामना कर रहा है जिसे निकट भविष्य में गिरफ्तार किए जाने की संभावना नहीं है। इसलिए, लचीला और टिकाऊ कृषि और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने की तत्काल आवश्यकता है। यह एक व्यापक अवधारणा, समन्वय, सहयोग और दृष्टि और शिक्षा और विज्ञान से लेकर अभ्यास और निर्णय लेने तक सभी हितधारकों को शामिल करने की मांग करता है[58]।

इस संदर्भ में, अध्येता उजबेकिस्तान और भारत के बीच "भाई शहरों" की एक परियोजना शुरू करना उचित समझता है, जहां समान चुनौतियां और मुद्दे प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, उजबेकिस्तान में खोरेज़म और मुयनक क्षेत्र, जो अरल सागर बेसिन के करीब स्थित हैं और जहां स्थानीय नीतियां मुख्य रूप से जलवायु से संबंधित चुनौतियों का मुकाबला करने पर केंद्रित हैं।

अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देना

एससीओ अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता के महत्व को पहचानता है और क्षेत्रों में संयोजकता बढ़ाने के लिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) जैसे बाहरी भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। संयोजकता पहल को संरेखित करना और मानकों और नियमों को सुसंगत बनाना निर्बाध व्यापार, परिवहन और डिजिटल संयोजकता की सुविधा प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, लोगों के बीच

आदान-प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने से आपसी समझ को बढ़ावा मिल सकता है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को सुदृढ़ किया जा सकता है। अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देने में एससीओ के प्रयास अपने प्रभाव का विस्तार करने और अन्य क्षेत्रीय संगठनों और पहलों के साथ तालमेल बनाने के लिए आवश्यक हैं।

एससीओ अन्य क्षेत्रीय संगठनों, जैसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू), आसियान और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को सुदृढ़ कर सकता है। यह जुड़ाव परिवहन, व्यापार सुविधा और डिजिटल संयोजकता जैसे सामान्य हित के क्षेत्रों में सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और नीति समन्वय को बढ़ावा दे सकता है। रणनीतियों को संरेखित करके, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, और चर्चा के लिए मंच बनाकर, एससीओ इन संगठनों के साथ तालमेल बना सकता है और अधिक एकीकृत और जुड़े यूरेशियन स्पेस को बढ़ावा दे सकता है[59]।

अब तक, एससीओ ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ कई समझौता ज्ञापनों (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं। मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र और एससीओ के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एससीओ ने क्षेत्र में हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, सीएसटीओ (सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन) और एससीओ ने क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों को संयोजित करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। व्यापार, अर्थव्यवस्था, परिवहन और बुनियादी संरचना पर सहयोग बढ़ाने के लिए, ईसीओ (आर्थिक सहयोग संगठन) और एससीओ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए[60]।

उपर्युक्त क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने से तालमेल पैदा हो सकता है और अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष-एससीओ का भविष्य

अंत में, एससीओ की संयोजकता की वर्तमान स्थिति उपलब्धियों, चुनौतियों और अवसरों के मिश्रण को दर्शाती है।

एससीओ के भीतर क्षेत्रीय संयोजकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें परिवहन बुनियादी संरचना के विकास, मल्टीमॉडल परिवहन गलियारे, व्यापार सुविधा, ऊर्जा संयोजकता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल हैं। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, एससीओ वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के निर्बाध आंदोलन को बढ़ावा दे सकता है, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, और क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ कर सकता है।

अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देना एससीओ के लिए अपने प्रभाव का विस्तार करने, क्षेत्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करने और अन्य क्षेत्रीय संगठनों और पहलों के साथ तालमेल बनाने के लिए भी आवश्यक है।

संयोजकता पहलों को संरेखित करके, मानकों और विनियमों को सुसंगत करके, और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर, एससीओ सभी क्षेत्रों में निर्बाध संयोजकता को बढ़ावा दे सकता है। बाहरी भागीदारों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सक्रिय जुड़ाव सहयोग और समन्वय को बढ़ाएगा, जिससे एक अधिक एकीकृत और जुड़ा हुआ यूरेशियन अंतरिक्ष होगा। अंतर-क्षेत्रीय संयोजकता को प्राथमिकता देकर, एससीओ क्षेत्रीय सहयोग के भविष्य को आकार देने और आपसी समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस तरह के नियमित और गहन राजनीतिक संवाद पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ समन्वय और सहयोग, साथ ही बाहरी भागीदारों के साथ जुड़ाव, एक अच्छी तरह से जुड़े और समृद्ध एससीओ क्षेत्र की दृष्टि को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एससीओ का भविष्य का प्रक्षेपवक्र इसके सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगा। चुनौतियों का सामना करके, अवसरों का लाभ उठाकर और सहयोग को गहरा करके, एससीओ अपने क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग के माध्यम से, एससीओ एक जुड़े और समृद्ध क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकता है जो वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास में योगदान देता है।

दो दशकों से भी कम समय में, एससीओ एक प्रमुख यूरेशियन निर्माण के रूप में उभरा है। सुरक्षा खतरों को संबोधित करने पर इसका प्राथमिक ध्यान इसकी सदस्यता के लिए एक स्थायी आधार बना हुआ है। जबकि संगठन ने आर्थिक विकास, संयोजकता और ऊर्जा सहयोग को शामिल करने के लिए अपने उद्देश्यों का विस्तार किया है, परिणाम विविध रहे हैं। एससीओ का उद्देश्य अब अपने क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक प्रोफाइल को बढ़ाना है। नए सदस्यों का समावेश यूरेशिया से परे संगठन की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है। जैसा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है, एससीओ इस परिवर्तन का एक प्रासंगिक स्तंभ बन गया है। हालांकि, 21वीं सदी को वास्तव में एक एशियाई सदी के रूप में मान्यता देने के लिए, एक प्रभावी क्षेत्रीय सहकारी तंत्र एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, और यकीनन, एससीओ एशियाई लोगों के लिए, एशियाई लोगों द्वारा और एशियाई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में काम कर सकता है।

> एससीओ का उद्देश्य अब अपने क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक प्रोफाइल को बढ़ाना है। नए सदस्यों का समावेश यूरेशिया से परे संगठन की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है। जैसा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है, एससीओ इस परिवर्तन का एक प्रासंगिक स्तंभ बन गया है।

> एससीओ की भारत की अध्यक्षता ने दिखाया है कि संगठन एक सांस्कृतिक-मानवीय और परिवहन-आर्थिक सहयोग में बदल रहा है। यह दृष्टिकोण निस्संदेह एससीओ के सदस्य देशों को एक साथ लाने, साझेदार देशों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान को सुदृढ़ करने और तनाव को कम करने और उन देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने का कार्य करता है जिनके साथ उनके हितों का टकराव है। यह दृष्टिकोण निकट भविष्य में एससीओ सदस्य देशों की विदेश नीति के एजेंडे में बना रहेगा।

एससीओ के भीतर सहयोग उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की संभावना है जहां अधिकांश सदस्य राष्ट्रों के हित एकजुट होते हैं और वे अपनी ताकत का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आतंकवाद, चरमपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना शामिल है।

यद्यपि एससीओ को मूल रूप से अफगानिस्तान में सामाजिक-राजनीतिक जीवन को हल करने और आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने के लिए एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके कार्यों और कार्यों में आज तक महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अफगान समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के अलावा, आज यह सदस्य देशों के लिए आर्थिक सहयोग, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक सार्वभौमिक मंच बन गया है।

यह कोई रहस्य नहीं है कि एससीओ की सदस्यता धीरे-धीरे बढ़ रही है और संगठन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इसके हित बदल रहे होंगे। परिवर्तन और रुझानों से संकेत मिलता है कि एससीओ, एक बार अफगानिस्तान में सामाजिक-राजनीतिक जीवन तय हो जाने के बाद, विभिन्न कार्यों की सेवा करेगा, क्योंकि इस संगठन का कोई भी देश एससीओ को सैन्य ब्लॉक के प्रोटोटाइप के रूप में उपयोग नहीं करेगा। एससीओ की भारत की अध्यक्षता ने दिखाया है कि संगठन एक सांस्कृतिक-मानवीय और परिवहन-आर्थिक सहयोग में बदल रहा है। भारत ने मुख्य रूप से "सॉफ्ट पावर" और "छवि बनाने" पर ध्यान केंद्रित किया है, और सांस्कृतिक और मानवीय परियोजनाओं और अंतर-सांस्कृतिक संचार का आयोजन और समर्थन किया है। यह दृष्टिकोण निस्संदेह एससीओ सदस्य देशों को एक साथ लाने, साझेदार देशों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान को सुदृढ़ करने और तनाव को कम करने और उन देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने का कार्य करता है जिनके साथ उनके हितों का टकराव है। यह दृष्टिकोण, संगठन के भीतर और साथ ही क्षेत्रों के बीच अंतर्संबंध को भी सुदृढ़ करता है। अध्येता का सुझाव है कि यह दृष्टिकोण निकट भविष्य में एससीओ सदस्य राष्ट्रों की विदेश नीति के एजेंडे पर बना रहेगा।

जबकि एससीओ की क्षमता बहुत अधिक बनी हुई है, इसके वास्तविक प्रभाव का अभी भी आकलन किया जा रहा है। संगठन यूरेशिया की रणनीतिक वास्तुकला के एक प्रमुख तत्व के रूप में जारी रहने की संभावना है।

- नूरिम्बेतोव, आर (2022)। "बदलती दुनिया और शंघाई सहयोग संगठन".ART VERNISSAGE press. 4-6.
- https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/india-and-the-एससीओ-a-vision-for-expanding-new-delhi-s-engagement/
- https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8919&lid=5817
- https://uzdaily.uz/en/post/75649
- https://www.researchgate.net/publication/342916396_The_Expanding_Role_of_the_Shanghai_Cooperation_Organization_in_the_Context_of_Inter-Regional_Integration_between_Central_Asia_and_South_ Asia_Prospects_and_Challenges
- https://www.un.org/en/chronicle/article/role-shanghai-cooperation-organization-counteract-ing-threats-peace-and-security
- https://moderndiplomacy.eu/2019/01/31/एससीओ-external-relations-and-focus-on-regional-cooperation/
- https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/india-and-the-एससीओ-a-vision-for-expanding-new-delhi-s-engagement/ https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/Articles/202112/t20211203_8276.html
- https://kun.uz/en/news/2022/05/07/एससीओ-member-states-to-discuss-prospects-for-strengthening-international-transport-connectivity-in-khiva
- https://kun.uz/en/news/2023/04/24/uzbekistan-delegation-takes-part-in-xi-meeting-of-department-heads-of-एससीओ-member-states-involved-in-preventing-and-eliminating-emergencies-in-delhi
- https://kun.uz/en/news/2023/03/09/mirziyoyev-approves-international-agreement-on-irans-accession-to-the-एससीओ
- https://articlekz.com/en/article/34676
- https://www.eurasiareview.com/09082021-the-recent-shanghai-cooperation-organization-एससीओ-meeting-outcomes-and-implications-oped/
- https://uwidata.com/26675-the-एससीओs-samarkand-declaration/
- https://thekabultimes.com/the-recent-shanghai-cooperation-organization-एससीओ-meeting-out- comes-and-implications/

- https://www.newscentralasia.net/2021/07/19/international-conference-on-the-possibilities-of-com-prehensive-connectivity-between-central-and-south-asia-outcomes/
- इना रुडेंको, जॉन पीए लामर्स, संजर दावलेटोव और सरदोर खोदजानियाज़ोव। शिक्षा, विज्ञान और उससे परे के माध्यम से ग्रामीण उजबेकिस्तान में सतत विकास//सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक और व्यावहारिक सम्मेलन शिक्षा और विज्ञान। ताशकंद, उजबेकिस्तान, 6-8 अप्रैल 2016. P.119-120.
- CAREC Program - CAREC Institute
- https://articlekz.com/en/article/34676
- शंघाई सहयोग संगठन | एससीओ (sectएससीओ.org)
- policy.asiapacificenergy.org

पाद-टिप्पणियाँ

[1]“2006 एससीओ शिखर सम्मेलन के संयुक्त विज्ञप्ति का पूर्ण पाठ, 15 जून, 2006, http://www.china.org.cn/english/features/meeting/171590.htm.

[1]“एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर दुशान्बे घोषणा, "17 सितंबर, 2021, http://eng.sectएससीओ.org/news/20210917/782639. html.

[2]“भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित "साइबर स्पेस फ्रंटियर्स को सुरक्षित करना" पर आरएटीएस एससीओ व्यावहारिक संगोष्ठी, 15 दिसंबर, 2022, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883880

[3]关于上海合作组织反恐机构，https://ecrats.org/cn/about/history/

[4]推动构建更加紧密的上合组织命运共同体”，人民网，2022年9月13日，http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2022-09/13/nw.D110000renmrb_20220913_2-03.htm

[5]“एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के उपायों को मंजूरी देती है, "एएनआई, 14 अक्तूबर, 2022, https://www.aninews.in/news/world/asia/एससीओs-regional-anti-terrorism-structure-approves-measures-to-counter-threats-posed-by-terror-groups-operating-from-afghanistan20221014152014/

[6]张文伟，“上海合作组织信息安全合作：必要性、现状及前景”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2016年第3期，第101页。

[7]“संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र और एससीओ के बीच सहयोग पर प्रस्ताव पारित किया, "31 मार्च, 2021, http://eng.sectएससीओ.org/news/20210330/737245.html

[8]李益斌，“上海合作组织的网络恐怖主义治理探究”，《网络空间战略论坛》，2021年8月，第88页。

[9]张文伟，“上海合作组织信息安全合作：必要性、现状及前景”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2016年第3期，第104页。

[10]张莹秋，“上合组织信息安全合作”，《信息安全与通信保密》，2022年第8期，第142页。

[11]http://en.kremlin.ru/catalog/persons/351/events/66706

[12]दस्तावेज|एससीओ (sectएससीओ.org)

[13]सरकारी परिषद के एससीओ प्रमुखों की बैठक। (2023, 3 जून)). http://government.ru/en/news/46943/

[14]एससीओ ऊर्जा क्लब: यह क्या होना चाहिए? एससीओ शंघाई सहयोग संगठन [डिजिटल संसाधन]। URL: http://infoshos.ru/ en/?idn=9616 (accessed: 04.06.2023).

[15]दस्तावेज़|एससीओ (sectएससीओ.org)

[16]https://एससीओ-russia2020.ru/images/17/25/172532.pdf

[17]एससीओ-सफल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक नया मॉडल। (14 जून 2006,)। रूस के राष्ट्रपति। http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23633

[18]https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/20080520/एससीओ-forum-meets-beijing-discuss-cooperation-issues

[19]सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का पूर्ण सत्र। (2016, 17 जून)। रूस के राष्ट्रपति। http://en.kremlin.ru/events/ president/news/52178

[20]शंघाई सहयोग संगठन: वैश्विक मामलों में एक नई भूमिका//रूस की तलाश में [डिजिटल संसाधन]। URL: https://eng.globalaffairs.ru/articles/shanghai-cooperation-organization-looking-for-a-new-role/ (accessed: 04.06.2023).

[21]एससीओ राष्ट्र परिषद के प्रमुखों//रूस के राष्ट्रपति की बैठक [डिजिटल संसाधन]। URL: http://en.kremlin.ru/events/president/ news/66706 (accessed: 04.06.2023).

[22]दीर्घकालिक पड़ोसी, मित्रता और सहयोग पर एससीओ का समझौता [डिजिटल संसाधन]। URL: https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=20606 (accessed: 04.06.2023).

[23]शंघाई सहयोग संगठन|एससीओ [डिजिटल संसाधन]. URL: http://eng.sectएससीओ.org/news/20201208/702292.html (accessed: 04.06.2023).

[24]https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/afghanistans-drug-trade-is-booming-under-taliban-rule/

[25]https://www.trtworld.com/magazine/after-decades-of-war-afghanistan-s-drug-trade-booms-like-never-before-46284

[26]https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf

[27]https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2022/June/unodc-report_-over-one-billion-methamphetamine-tablets-seized-in- east-and-southeast-asia-in-2021-as-the-regional-drug-trade-continues-to-expand.html

[28]https://www.world-today-news.com/caught-and-then-the-godfather-sam-gore-a-giant-drug-dealing-across-asia/

[29]https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf

[30]https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13011-021-00375-w

[31]https://www.acic.gov.au/sites/default/files/2020-08/iddr_2015-16_clandestine_laboratories_and_precursors.pdf

[32]https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2021/9.1_Clandestine_laboratories_detected_and_dismantled.pdf

[33]https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/drug-purity

[34]https://www.incb.org/documents/PRECURSORS/RED_LIST/2020/Red_List_2020_E.pdf

[35]https://geti2p.com/en/

[36]https://www.darknet.org.uk/2023/03/privacy-implications-of-web-3-0-and-darknets/

[37]https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/4349a4ee-cac4-440e-9d39-d2c21869e49a

[38]https://theconversation.com/darknet-markets-generate-millions-in-revenue-selling-stolen-personal-data-supply-chain-study-finds-193506

[39]https://www.swansea.ac.uk/media/The-Rise-and-Challenge-of-Dark-Net-Drug-Markets.pdf

[40]https://theconversation.com/darknet-markets-generate-millions-in-revenue-selling-stolen-personal-data-supply-chain-study-finds-193506

[41]https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10610-016-9329-7.pdf

[42]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300216

[43]https://www.palantir.com/index.html

[44]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2666281720303954

[45]नूरिम्बेतोव, आर (2022)। "बदलती दुनिया और शंघाई सहयोग संगठन".ART VERNISSAGE press. 4-6.

[46]https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29971/English_translation_of_Prime_ Ministers_Intervention_in_Extended_Plenary_of_18th_एससीओ_Summit_June_10_2018

[47]https://www.newscentralasia.net/2021/07/19/international-conference-on-the-possibilities-of-comprehensive-connectivity-between-central-and-south-asia-outcomes/

[48]https://uwidata.com/26675-the-एससीओs-samarkand-declaration/

[49]https://daryo.uz/en/2023/01/12/voice-of-global-south-summit-uzbek-president-promotes-initiatives-aimed-at-supporting-developing-countries. https://www.youtube.com/watch?v=b6SfLcHiERs

[50]https://uzdaily.uz/en/post/75649

[51]https://uza.uz/en/posts/uzbekistan-hosts-the-ninth-meeting-of-एससीओ-transport-ministers_371839

[52]https://news.bharattimes.co.in/nitin-gadkari-chairs-the-meeting-of-transport-ministers-of-shanghai-cooperation-organization/

[53]https://www.newscentralasia.net/2021/07/19/international-conference-on-the-possibilities-of-comprehensive-connectivity-between-central-and-south-asia-outcomes/

[54]दो ऊर्जा परियोजनाएं-तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस पाइपलाइन, और मध्य एशिया दक्षिण एशिया विद्युत संचरण और व्यापार परियोजना (CASA-1000) जो ताजिक और किर्गिज़ जलविद्युत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाने की आशा है, और मध्य एशिया-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार (CASAREM) में विकसित होगी, एक बार नियोजित मध्य एशियाई जल विद्युत क्षमता धारा में आ जाने के बाद, एक क्षेत्र-व्यापी ऊर्जा विनिमय की सुविधा प्रदान कर सकती है।

[55]https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/india-and-the-एससीओ-a-vision-for-expanding-new-delhi-s-engagement/

[56]https://daviscenter.fas.harvard.edu/sites/default/files/files/2021-10/Digital_Silk_Road_Report_2021.pdf

[57]https://cabar.asia/en/tajikistan-and-south-asia-how-does-the-multi-vector-foreign-policy-work

[58]https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8919&lid=5817

[59]https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8919&lid=5817

[60]इना रुडेंको, जॉन पीए लामर्स, संजर दावलेटोव और सरदोर खोदजानियाज़ोव। शिक्षा, विज्ञान और उससे परे के माध्यम से ग्रामीण उजबेकिस्तान में सतत विकास//सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक और व्यावहारिक सम्मेलन शिक्षा और विज्ञान। ताशकंद, उजबेकिस्तान, 6-8 अप्रैल 2016. P.119-120.

[61]https://articlekz.com/en/article/34676

[62]https://moderndiplomacy.eu/2019/01/31/एससीओ-external-relations-and-focus-on-regional-cooperation/

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय वैश्विक परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। परिषद आज एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियाँ आयोजित करती है और प्रकाशन करती है। इसमें सुभंडारित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका का प्रकाशन करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा दिया जा सके और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी है।

भारतीय वैश्विक
परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली